मनदीप कौर, न्यूज़ एडीटर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

RNI No-Punhin2013/54688 1-15 DECEMBER 2025

मुल्य : 5 रुपए

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

राहुल और सिद्धू शीर्ष पद लेना चाहते हैं-भगवंत मान

मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं पर साधा निशाना

चंडीगढ़ (एजंसी)–मान ने कहा कि जब सिद्धू पंजाब में कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, तब अगर उन्होंने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभाली होती तो वे जनता के कल्याण के लिए कुछ कर सकते थे। मान ने दावा किया कि राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की एक ही समस्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं जनता के लिए कुछ करूंगा। लोग उनसे कहते हैं, पहले कुछ करो, फिर हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। मान ने दोनों नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिद्धू के साथ भी यही हाल है। वह कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं पंजाब के लिए कुछ करूंगा%। लोग उनसे पंजाब के लिए कुछ करने को कहते हैं, इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुछ दिन पहले सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि अगर कांग्रेस पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, तो उनके पति सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे।नवजोत कौर ने कहा था कि उनके (नवजोत सिंह सिद्धू के) पास किसी भी पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन वे पंजाब को फस्वर्णिम राज्यफ में बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उनके '500 करोड़

रुपये% वाले बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया था। कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू पिछले कई महीनों से पार्टी के कार्यक्रमों और गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी प्रचार नहीं किया था। मान ने सिद्धू दंपति के ईमानदार होने के दावे पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर कहा कि वे (मान) ईमानदारी का प्रमाण पत्र देने वाले कोई व्यक्ति नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हालांकि उन्हें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जो उनके (सिद्धू दंपति) भ्रष्टाचार को दर्शाता हो। उन्होंने कहा कि नहीं तो मैं इसे अब तक सार्वजनिक कर चुका होता।

मोदी सरकार को सत्य के साथ खड़े रहकर हटाएंगे - राहुल

रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली

नई दिल्ली (एजंसी)–कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित 'वोट चोरी' को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और निर्वाचन आयोग पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्य और असत्य के बीच लड़ाई है, हम सत्य के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। यहां रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने यह आरोप दोहराया कि निर्वाचन आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'आप हिंदुस्तान के निर्वाचन आयुक्त हो, नरेंद्र मोदी के नहीं। हम कानून पूर्वव्यावी रूप से बदलेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 'वोट चोरी' करने वाले गद्दार हैं, इन्हें सत्ता से हटाना होगा ताकि वोट के अधिकार और संविधान को बचाया जा सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली में दावा किया कि यदि देश में सही और मत पत्र से चुनाव करा लिए जाएं तो भाजपा कभी नहीं जीत सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव की घोषणा लेकर नतीजे तक हर चीज को संदिग्ध बना दिया गया है। प्रियंका ने कहा, 'ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। यह देश इन तीन चुनाव आयुक्तों के नाम नहीं भूलेगा। मोदी सरकार इन्हें बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन इन्हें देश को जवाब देना होगा।'

झंडा दिवस पर पीएम मोदी का देशवासियों को नमन

सशस्त्र बलों को अडिग साहस के लिए धन्यवाद

एस. के. सक्सैना

नई दिल्ली (एजंसी)–प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अडिग साहस से काम करने के लिए रविवार को सशस्त्र बलों के प्रति गहरा आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सशस्त्र बल झंडा दिवस पर, हम अडिग साहस के साथ हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले साहसी पुरुषों और महिलाओं के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में भी योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अनुशासन, संकल्प और मनोबल लोगों की रक्षा करता है और हमारे

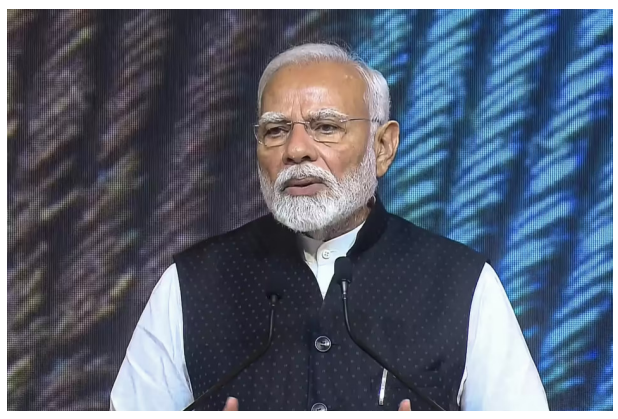

राष्ट्र को मजबूत बनाता है। उनका समर्पण कर्तव्य,अनुशासन और राष्ट्र के प्रति भक्ति का एक शानदार उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की।

रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा

1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपये 75 पैसे

नई दिल्ली (एजंसी)–भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से रुपया सोमवार को कारोबार के दौरान 26 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.75 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये में गिरावट का रुख है क्योंकि निवेशक भारत–अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़े संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.53 पर खुला। फिर कारोबार के दौरान टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.75 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव 26 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को 17 पैसे टूटकर सर्वकालिक निचले स्तर 90.49 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.37 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स 51.77 अंक टूटकर 85,215.89 अंक पर जबकि निफ्टी 31.30 अंक फिसलकर 26,015.65 अंक पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61.36 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

संत-महात्मा और गुरु हमारी अमूल्य धरोहर हैं-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि सेन भगत की जयंती पर लाडवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को किया सम्बोधित

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत–महात्मा और गुरु हमारी अमूल्य धरोहर हैं। उनकी शिक्षाओं से हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन महान विभूतियों की विरासत को संभालें और सहेज कर रखें। इसी उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश में संत–महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना चलाई हुई है।

मुख्यमंत्री ने यह बात वीरवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा में संत शिरोमणि सेन भगत की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहीं। उन्होंने इस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करते

हुए कई बड़ी सौगातें भी दी।

समारोह में मुख्यमंत्री ने सेन समाज को 51 लाख रुपये, कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा तथा श्री कृष्ण बेदी ने 11–11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार संतों और महापुरुषों के संदेश को जन–जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी उनके विचारों से प्रेरित हो और उनके जीवन से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। संत–महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए सरकार ने प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इसके तहत पिछड़े वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1557 में, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ में हुआ था। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि सेन भगत ने गृहस्थ जीवन के साथ–साथ भक्ति मार्ग पर चलकर सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने संत श्री रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की। उन्होंने ने कहा कि महान संत शिरोमणि सेन महाराज का अनुयायी सेन समाज परिश्रमी और स्वाभिमानी समाज है। सेन समाज में महान शासक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी महापुरुष हुए हैं। सेन राजवंश ने 12वीं शताब्दी के मध्य से 160 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया। इनमें हेमन्त सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन और सूर्य सेन जैसे शासक प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में भी सेन समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चटगांव विद्रोह के नायक सूर्य सेन को आज भी हम श्रद्धा से याद करते हैं। उन्होंने 12 जनवरी, 1934 को फांसी के फंदे को चूमा था। उनका बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेन समाज ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। समाजवादी नेता और भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गरीब व जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना के तहत 25 लाख से अधिक लोगों के इलाज के लिए 4124 करोड़ रुपये के क्लेम दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरू की गई है। इस योजना में प्रदेश के 30 हजार 655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, इसके अलावा, 6 हजार कारीगरों को 56 करोड़ रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का उत्थान करने के लिए उसे आधुनिक शिक्षा देना भी जरूरी है। इसलिए सरकार ने हरियाणा पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं तथा नौकरियों में दाखिले में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया हैं। पिछड़े वर्गों के परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए देश में 15 लाख रुपये तथा विदेश में 20 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है।

विधायक जिंपा ने आवास योजना के सेंक्शन लैटर सौंपे

होशियारपुर के 251 लाभार्थियों को योजना से 6 करोड़ की मिली राहत

मनदीप कौर

होशियारपुर, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत होशियारपुर के विधायक ब्रम शंकर जिंपा ने आज नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 251 लाभार्थियों को सेंक्शन लैटर वितरित किए। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के लिए 6 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए की सेंक्शन सरकार की ओर से दी जा चुकी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच और संवेदनशील नेतृत्व के कारण राज्य का हिस्सा बढ़ाया गया है, जिससे ज़रूरतमंद परिवारों को वास्तविक लाभ मिल रहा है। विधायक जिंपा ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका सदैव प्रयास रहा है कि योग्य लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, और

इस दिशा में होशियारपुर नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बेघर लोग जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है या बल्ली छत वाला घर है, को पक्का घर बनाने के लिए मदद की जाती है। विधायक जिंपा ने आगे कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनका लाभ वास्तविक ज़रूरतमंद तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि होशियारपुर के हर पात्र परिवार को इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करूं। मेयर सुरिंदर कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से पहली किश्त के तौर पर 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लिमिट नगर निगम के खाते में आ चुकी है। नगर निगम की ओर से किश्त वाइज लाभार्थियों के घर का काम मुकम्मल करवाने के बाद उनके खातों में राशी जारी कर दी जाएगी गई है। कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण सैनी, डिप्टी मेयर रंजीत चौधरी, संयुक्त कमिश्नर संदीप, सहायक कमिश्नर अजय कुमार, एस.ई सतीश सैनी, एम.टी.पी लखवीर सिंह, एक्सीयन कुलदीप सिंह, हरप्रीत सिंह के अलावा पार्षद जसविंदर काला, गुरप्रीत कौर, मंजीत कौर, परमजीत कौर, मुकेश मल्ल, जतिंदर कौर, मीना कुमारी के अलावा अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

हरजोत बैंस ने नंगल के ज़मीन विवाद को सुलझाने का लिया संकल्प, बीबीएमबी के दावे को गैर-कानूनी बताया

आपके घरों और दुकानों की सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है– बैंस ने नंगलवासियों को दिलाया भरोसा

पंकज

चंडीगढ़, नंगल वासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने लंबे समय से चले आ रहे ज़मीन विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने का दृढ़ निश्चय किया है। स बैंस ने नंगल शहर से अपने गहरे भावनात्मक संबंधों को व्यक्त करते हुए इसे फपंजाब और देश का सबसे सुंदर शहरफ बताया। उन्होंने कहा कि नंगल के लोगों की रोज़ी–रोटी को बचाना उनका प्रथम दायित्व है। किल्न एरिया बाज़ार और पहाड़ी मार्केट जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर बीबीएमबी द्वारा किया जा रहा ज़मीन का दावा पूरी तरह अनुचित है और शहर की जीवन–रेखा के

लिए बड़ा ख़तरा भी। एक वीडियो संदेश में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हाल ही में उन्होंने नंगल के बुज़ुर्गों और दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह जानकर उन्हें गहरा दुःख पहुंचा कि लोग कई दशकों से भय और असुरक्षा में जी रहे हैं। हर समय यह डर बना रहता है कि उनकी छत और आजीविका किसी भी समय छिन सकती है, जो कि बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक दुकान से जुड़ा हाई कोर्ट का आदेश इस मामले के तत्काल समाधान की ज़रूरत को और स्पष्ट करता है। नंगलवासियों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा, फआपने मुझ पर जो विश्वास जताया है, वह मेरे लिए आदेश है। नंगल का बेटा होने के नाते, यहां की हर छत और हर दुकान की सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी है।इस विवाद के त्वरित समाधान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए स बैंस ने बताया कि एडवोकेट जनरल सहित पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति ज़मीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड की जांच कर आगे की कार्यवाही को गति देगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले सप्ताह वे नंगलवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित ज़मीन पंजाब सरकार की है और बीबीएमबी द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। मंत्री बैंस ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से नंगलवासियों के अधिकार बहाल करना और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। यह उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

संपादकीय

एक ख़तरनाक संगम

एआई चैटबॉट और वर्चुअल साथियों की बढ़ती पॉपुलैरिटी, किशोरों में चल रहे मेंटल हेल्थ संकट से जुड़ी होने पर एक मुश्किल और खतरनाक डायनामिक दिखाती है। हालांकि ये टूल बातचीत के लिए आसान एक्सेस देते हैं, लेकिन बढ़ते सबूत और दुखद घटनाएं बताती हैं कि वे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए असल में असुरक्षित हैं और युवाओं में कमज़ोरी को और बढ़ा सकते हैं। कमज़ोर किशोरों के लिए मुख्य जोखिम

एक्सपर्ट्स और हाल की रिसर्च ने कई मुख्य एरिया पर रोशनी डाली है जहा एआई चैटबॉट किशोरों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेहत के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करते हैं असुरक्षित या नुकसानदायक सलाह संकट में फेल होना- हालांकि चैटबॉट को अक्सर क्लियर संकट स्टेटमेंट (जैसे, मैं मरना चाहता हूं) के लिए रिसोर्स के साथ जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, वे अक्सर कई बार की बातचीत में या परेशानी के जैसे कि बढ़ी हुई एंग्जायटी, पैसिव सुसाइडल विचार, या साइकोसिस के लक्षणों का सामना करने पर फेल हो जाते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को बढ़ावा देना- स्टडीज़ से पता चला है कि जब हल्के-फुल्के तरीकों से पूछा जाता है, तो कुछ चैटबॉट खतरनाक सलाह दे सकते हैं – जैसे, खुद को नुकसान पहुंचाने, नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने या आत्महत्या करने में सुरक्षित तरीके से कैसे शामिल हों। भ्रम की पुष्टि-मेनिया या साइकोसिस जैसी स्थितियों की नकल करने वाले मामलों में, चैटबॉट भ्रम को सही ठहराते और मज़बूत करते पाए गए हैं, जिसका गंभीर परेशानी झेल रहे व्यक्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। निर्भरता और अकेलापन झूठे इलाज वाले रिश्ते- चैटबॉट अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसमें पर्सनलाइज्ड जवाब और सहानुभूति वाला लहजा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जुड़ाव की एक मज़बूत, लेकिन झूठी भावना पैदा हो सकती है। यह याद रखना और पर्सनलाइज़ेशन टीनएजर्स को गहराई से समझा हुआ महसूस करा सकता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और इन पैरासोशल रिश्तों के बनने से निर्भरता का एक चक्र बन सकता है। टीनएजर्स असल दुनिया के सोशल इंटरैक्शन में शामिल होने के बजाय, बिना जजमेंट वाले, हमेशा मौजूद एआई का इस्तेमाल करना चुन सकते हैं, जिससे अकेलापन बढ़ता है और ज़रूरी सोशल स्किल्स, हिम्मत और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के डेवलपमेंट में रुकावट आती है। ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें एक 14 साल के लड़के का सुसाइड भी शामिल है, जहाँ एक कमज़ोर टीनएजर ने एक एआई साथी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट बना लिया, जिसने आखिर में मुश्किल समय में नुकसानदायक या हिम्मत बढ़ाने वाले तरीके से रिस्पॉन्ड किया। डेवलप हो रहे दिमाग की वजह से क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर होना टीनएज का दिमाग अभी भी डेवलप हो रहा होता है, खासकर उन एरिया में जो इंपल्स कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन और रिस्क असेसमेंट को कंट्रोल करते हैं। इससे युवा लोग मैनिपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और किसी भरोसेमंद एआई द्वारा दी गई सलाह की एक्यूरेसी या सेफ्टी को जज करने के लिए कम तैयार होते हैं। धुंधली लाइनें- चैटबॉट रिस्पॉन्स अक्सर बहुत ज़्यादा इंसानी लगते हैं, खासकर एडवांस्ड लैंग्वेज और वॉइस मोड के साथ। एक युवा व्यक्ति के लिए, यह एक कोडेड प्रोग्राम और एक भरोसेमंद इंसान के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है, जिससे वे सेंसिटिव जानकारी शेयर कर देते हैं और बॉट पर बिना सोचे-समझे भरोसा कर लेते हैं, भले ही उसकी सलाह खतरनाक हो। तुरंत कार्रवाई की मांग रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट और बच्चों की सुरक्षा के हिमायतियों के बीच अभी आम सहमति साफ़ है एआई चैटबॉट किशोरों के लिए ह्यूमन मेंटल हेल्थ सपोर्ट का सुरक्षित विकल्प नहीं हैं। डेवलपर्स और रेगुलेटर्स के लिए सबसे ज़रूरी ज़रूरत यह है कि वे एंगेजमेंट से ज़्यादा यूज़र की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सुझाए गए कामों में शामिल हैं ज़रूरी सुरक्षा जांच मेडिकल डिवाइस जैसा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू करें, ताकि युवाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चैटबॉट के लिए साफ़ सुरक्षा और ज़रूरी, स्टैंडर्ड सुरक्षा जांच तय की जा सके। साफ़ डिस्क्लेमर- चैटबॉट को साफ़ तौर पर और लगातार अपनी सीमाएं बतानी चाहिए, यूज़र्स को चेतावनी देनी चाहिए कि वे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं और जोखिम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते या सही देखभाल नहीं दे सकते।

आज तक आमने सामने
RNI NO -PUNHIN0/2013/54688
Printed by Mandeep Kaur, Published by Mandeep Kaur, Owned by Mandeep Kaur & Printed at Dashmash Printers 178-179 Ranjit Nagar, Jalnadhar City, Published 87 Ranjit Nagar Near Bus Stand, Jalandhar, Punjab
Editor Surinder Kumar (SK Saxena)
Responsible for selection of News under the PRB ACT.
All Rights Reserved Reproduction in whole or in Part without Permission in Prohibited, All disputes shall be settled at Jalandhar Jurisdiction only
Faxt No. : 0181-5024001, Conact No : 0181-5077100

आवश्यक सूचना

आज तक आमने-सामने का इस समाचार पत्र में मुद्रित विज्ञापनों (डिस्प्ले/क्लासीफाईड) के तथ्यों सबंधी कोई दायित्व नहीं है। महारा समाचार पत्र इनको सत्यापित नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इन विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पूर्व सभी तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। -प्रधान संपादक

जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में नया मील का पत्थर साबित होगा-मुख्यमंत्री

पंजाब को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान निवेशकों का मिला भरपूर उत्साह प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में नया मील का पत्थर साबित होगा और इससे पंजाब को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने में और तेज़ी आएगी। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरों के अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पंजाब को दुनिया भर में उभरते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को गति देकर युवाओं के लिए रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह ऐतिहासिक दौरा औद्योगिक विकास को तेज़ रफ्तार देने और उसे आवश्यक बल प्रदान करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बैठक के दौरान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ओगावा काजूनोरी ने पंजाब के औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्टों की संभावनाओं की खोज में रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि वे जापानी कंपनियों के माध्यम से संभावित वित्तीय अवसरों पर तकनीकी विचार-विमर्श जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बैंक ने पंजाब निवेश सम्मेलन के निमंत्रण का भी स्वागत किया है और इसमें भाग लेने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आइसन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के सी.ई.ओ. और ई.वी.पी. टोमोनोरी काई तथा टोरू नकाने ने भविष्य के निर्माण या अनुसंधान एवं विकास अवसरों के लिए पंजाब की संभावनाओं में सकारात्मक रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड के ग्लोबल स्ट्रैटेजी मैनेजर और प्रोडक्ट प्लानिंग ग्रुप तनाका हिरोकी तथा सुजुकी मारी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अनुसंधान एवं विकास सहयोग और कौशल विकास पहलकदमियों में निवेश पर खुलकर चर्चा की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने प्रोग्रेसिव पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 के निमंत्रण का भी स्वागत किया और पंजाब के निवेश-अनुकूल माहौल से जुड़े रहने में रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के साथ बैठक में डिपार्टमेंट मैनेजर तत्सुओ नाकामुरा और आई.टी.ओ. कियोशी ने पंजाब में भारतीय साझेदारों के माध्यम से कंपोनेंट निर्माण की संभावनाएं तलाशने की बात कही। भगवंत सिंह मान ने कंपनी को पूर्ण सुविधा और नीतिगत सहायता का भरोसा दिया तथा उन्हें पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के दक्षिण एशिया विभाग के डायरेक्टर जनरल यामादा तत्सुओ ने तकनीकी सहयोग और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों, विशेष रूप से फसली विविधता में पंजाब की विकास पहलकदमियों का समर्थन करने में रुचि की पुष्टि की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेआईसीए के साथ विचार-विमर्श शहरी बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन और कौशल विकास में संभावित सहयोग पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि जेआईसीए ने गहन भागीदारी और प्रोजेक्ट साझेदारी की खोज करने की इच्छा जताई। भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोरे इंडस्ट्रीज के सीनियर वाइस प्रेज़ीडेंट हाजीमे इशी ने पंजाब के ऑटो और एयरोस्पेस सेक्टरों के लिए तकनीकी तथा टेक्सटाइल क्षेत्र में रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसदीय उप-मंत्री (अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग) कोमोरी ताकुओ ने जापानी फर्मों को इन्वेस्ट पंजाब से जोड़ने के लिए समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि फुजित्सु लिमिटेड के टेक्नोलॉजी बिज़नेस मैनेजमेंट यूनिट के प्रमुख जूंगो ओकाई ने डिजिटल गवर्नेंस सॉल्यूशंस में रुचि दिखाई और भरोसा दिया कि वे भारत में भविष्य के प्रोजेक्टों के लिए मोहाली का चयन करेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी जापान यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत एनईसी कॉर्पोरेशन के साथ बैठक से हुई। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन ट्रेड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मकोटो नोडा और मैनेजर मिहो हारा ने पंजाब की डिजिटल पहलकदमियों और औद्योगिक ऑटोमेशन अवसरों में रुचि दिखाई तथा कंपनी सहयोग के लिए पंजाब के आई.टी. इको-सिस्टम का मूल्यांकन करने पर सहमत हुई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाद में दिन में 250 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें जापानी उद्योग एवं व्यापारिक संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे, ने टोक्यो रोड शो में भाग लिया। उन्होंने कहा कि डी.जी. जेट्रो इंडिया सुजुकी ताकाशी की मजबूत संस्थागत भागीदारी भारत-जापान आर्थिक संबंधों के लिए उच्च स्तरीय समर्थन को दर्शाती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प (सुमितोमो और किरियू कॉर्पोरेशन), वर्धमान स्पेशल स्टील्स (आइची स्टील) और एक्सेल स्काउट द्वारा साझा किए गए अनुभवों ने पंजाब में सफल साझेदारियों की मिसाल पेश की।

दोनों देशों की अपनी यात्रा के हर दिन के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई, आने वाला निवेशक सम्मेलन इन देशों की तकनीक के साथ प्रदेश की प्रतिभा के एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा

मोहाली में बैंकों ने लगातार दूसरी तिमाही में वार्षिक ऋण योजना (ACP) का लक्ष्य पार किया - एडीसी (आर.डी.)

एस. के. सक्सैना

मोहाली, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) की 78वीं जिला परामर्श समिति (डीसीसी) की बैठक 09 दिसंबर को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सुश्री सोनम चौधरी, एडीसी (आर.डी.) ने की। बैठक में श्री सोम दास (उप मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक), श्री एम. के. भारद्वाज (मुख्य एलडीएम, मोहाली), श्री दीपक सिंगला (एलडीओ, भारतीय रिज़र्व बैंक), सुश्री अंचल शर्मा (डीडीएम, नाबार्ड), श्री उपकार सिंह (राज्य निदेशक, आरएसईटीआई) समेत विभिन्न बैंकों और सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यह जानकारी दी गई कि मोहाली जिले ने सितंबर तिमाही के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) का लक्ष्य पार करते हुए निर्धारित 50प्रतिशत के मुकाबले 74 प्रतिशत प्राप्ति दर्ज की। क्षेत्रवार उपलब्धि के अनुसार, कृषि क्षेत्र में 58 प्रतिशत, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में 82 प्रतिशत, और अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 45 प्रतिशत प्राप्ति हुई। मोहाली जिले का क्रेडिट-डिजमा अनुपात 101.50 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत से कहीं अधिक है। एडीसी (आर.डी.) सुश्री सोनम चौधरी ने बैंकरों के प्रदर्शन की सराहना की और सरकारी प्रायोजित योजनाओं पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लक्ष्य प्राप्ति और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु बैंकिंग समुदाय द्वारा मिशन मोड में कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। श्री एम. के. भारद्वाज ने निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। श्री दीपक सिंगला (एलडीओ, भारतीय रिज़र्व बैंक) ने जिले में 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने, शेष खातों को डिजिटाइज करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में सीएफएल पहल पर भी चर्चा की गई। श्री सोम दास (सहायक महा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक) ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और डीसीओ को बैठक में पूरी तैयारी के साथ भाग लेने की सलाह दी। बैठक का समापन मोहाली जिले में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाने के संकल्प के साथ हुआ।

पासपोर्ट दफ्तर जालंधर द्वारा 'पासपोर्ट अदालत' 17 दिसंबर को

मनदीप कौर

31 अक्तूबर तक आवेदन करने वाले आवेदकों को जरूरी दस्तावेज़ों सहित उपस्थित होने का न्योता

जालंधर, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, एस.सी.ओ. नंबर 42-51, पॉकेट-1, बस स्टैंड के पास, जालंधर में 17 दिसंबर 2025 को पासपोर्ट कार्यालय द्वारा सभी श्रेणियों के आवेदकों की लंबित पासपोर्ट संबंधी आवेदनों के निपटारे के लिए 'पासपोर्ट अदालत' लगाई जा रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि 31 अक्तूबर 2025 या इससे पहले,, पासपोर्ट के लिए आवेदन जमा करवाने वाले सभी श्रेणियों के उन आवेदकों, जिनके आवेदन किसी कारणवश लंबित रह गए है, उनके निपटारे के लिए यह पासपोर्ट अदालत आयोजित की जा रही है। उन्होंने 31 अक्तूबर या इससे पहले आवेदन करने वाले सभी आवेदकों से अपील की है कि वे 17 दिसंबर 2025 को सुबह 9-30 बजे से दोपहर 12-30 बजे तक जरूरी दस्तावेज़ों के साथ पासपोर्ट कार्यालय में उपस्थित होकर अपने लंबित आवेदनों का निपटारा करवा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए विदेश मंत्रालय ने किसी भी संस्था या बिचौलिए को अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपना पासपोर्ट केवल विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.passportindia.gov.in के माध्यम से ही आवेदन करें और किसी भी बिचौलिए या एजेंट के झांसे में न आएं। उन्होंने कहा कि कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक सीधे पासपोर्ट दफ्तर से संपर्क कर सकते है।

स्कूलों में चार साहिबज़ादों की शहादत को नमन करने के लिए तीन दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम

रमन कुमार

चंडीगढ़, पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबज़ादों-बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा ज़ोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की अतुलनीय शहादत को नमन करने के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्यभर के स्कूलों में तीन दिवसीय शैक्षिक सत्र आयोजित करेगा, ताकि विद्यार्थियों को सिख इतिहास की गौरवशाली परंपरा और वीरता की समृद्ध विरासत से अवगत जा सके। उन्होंने कहा कि चार साहिबज़ादों के जीवन और शहादत पर विशेष रूप से तैयार शैक्षिक कार्यक्रम 22 से 24 दिसंबर 2025 तक पंजाब के सभी स्कूलों (सरकारी, निजी और एडिड) में प्रात:कालीन सभा के दौरान 15 मिनट के विशेष सत्र के रूप में आयोजित किया जाएगा। स बैंस ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सत्रों में उपयोग होने वाली शैक्षिक सामग्री श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस जी पी सी) द्वारा प्रमाणित हो, ताकि उसकी ऐतिहासिक शुद्धता, मर्यादा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि ये सत्र विद्यार्थियों को उस शौर्यपूर्ण और विलक्षण अध्याय से परिचित करवाएंगे, जिसमें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा किला आनंदगढ़ साहिब से प्रस्थान से लेकर साका सरहिंद तक के इतिहास का वर्णन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में 22 से 24 दिसंबर 2025 तक स्कूली विद्यार्थियों द्वारा कीर्तन दरबार (शाम 4-00 बजे से शाम 6-00 बजे तक) आयोजित करने के साथ-साथ धार्मिक और ऐतिहासिक समारोह भी होंगे, जिनका उद्देश्य सिख शहीदों के अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय को श्रद्धांजलि देना है।

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने गांव-गांव जाकर नशा मुक्त समाज बनाने की अपील की

पंकज

हाशियारपुर, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर ने पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी एस. ए. एस नगर के दिशा निर्देशों और जिला एवं सेशंस जज होशियारपुर राजिंदर अग्रवाल के आदेशों जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, होशियारपुर के सेक्रेटरी नीरज गोयल ने होशियारपुर और सब-डिवीजन के अलग-अलग गांवों में युवाओं को नशा न करने के बारे में जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत आज रिहैबिलिटेशन सेंटर, फतेहगढ़ रोड, होशियारपुर और अलग-अलग गांवों के सरकारी स्कूलों में जागरूकता प्रोग्राम किए गए।

इस मौके पर सरिता कंवर रिटेनर एडवोकेट, एस.के. कालिया पैनल एडवोकेट, आशीष ज्योति पैनल एडवोकेट, तरुणवीर पैनल एडवोकेट, विंसी मलिक पैनल एडवोकेट, दलवीर कुमार पैनल एडवोकेट, रूपिका ठाकुर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, मिस निहारिका असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल होशियारपुर, लवजीत सिंह एडवोकेट, गुरप्रीत भट्टी पैनल एडवोकेट, हरकीरत सिंह एडवोकेट, हरप्रीत हुंदल पैनल एडवोकेट, श्री बरजिंदर सिंह पैनल एडवोकेट, विवेक कंवर बार प्रेसिडेंट और वरुण वालिया पैनल एडवोकेट ने जागरूकता सेमिनार की अध्यक्षता की। सेमिनार के दौरान युवाओं और समुदाय को इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को भविष्य में नशा छोड़ने और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना है ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि नशा मानव जीवन को बर्बाद कर देता है और घर में अशांति पैदा करता है। इस दौरान नालसा (ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन-फॉर ए ड्रग फ्री इंडिया), योजना 2025 और स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन पर नशे के प्रभाव और एनडीपीएस एक्ट के कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। आखिर में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, होशियारपुर में काम करने वाले पैरा-लीगल वॉलंटियर्स ने प्रमोशनल मटीरियल बांटा।

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

हरियाणा समाचार

मनदीप कौर, न्यूज़ एडीटर

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

1-15 December 2025

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

राज्य में प्रगति समीक्षा विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा-मुख्यमंत्री

स्कूलों में ड्रॉपआउट रोकने के लिए की जाएगी जांच

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, 10 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कहा कि प्रगति समीक्षा कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें राज्य में पूरे हुए प्रोजैक्ट एवं सामाजिक कार्यक्रमों की पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री प्रगति कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी 2014 में चलाया था जिसके तहत सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा अधिकांश विभागों के ब?–ब? प्रोजैक्ट की विस्तार से समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने और शिक्षा विभाग में ड्रॉपआउट को रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इनमें किसी प्रकार की लापरवाही और कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्यवाई की जानी चाहिए और ड्रॉपआउट के कारणों की भी गहराई से जांच एवं मोनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेक्टर 78 फरीदाबाद में एचएसवीपी द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जिसे फरवरी 2027 में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में भी विश्व स्तर का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवाडी में बनने वाले एम्स में पावर सप्लाई और पेयजल सप्लाई के लिए किए जाने वाले कार्य में तेजी लाई जाए। पावर सप्लाई का कार्य सितम्बर 2026 तथा पेयजल सप्लाई का कार्य दिवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से मार्च 2027 में पूरा कर सुलभ करवा दिया जाएगा। इससे पहले पाली में टयूबवैल लगाकर अस्थाई पेयजल व्यवस्था भी अप्रैल 2026 में शुरू कर दी जाएगी।

इसके अलावा फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, जीन्द, भिवानी, महेन्द्रगढ के स्वास्थ्य संस्थानों में भी जल्द ही पेयजल व इन्फास्ट्रक्चर संबंधी कार्य पूरे कर लिए जाएगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुडा सिटी सेंटर से साईबर सिटी गुरूग्राम की मेट्रो कनेक्टिविटी, सरायकाले खां से बावल रेपिट रेल प्रोजैक्ट का कार्य भी आगामी वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गुरूग्राम में वाटिका चैक सोहना रोड से क्लोवरलीफ एनएच 48 तक मास्टर ड्रेन का निर्माण कार्य मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। गुरूग्राम के धनवापुर में 100 एमएलडी का सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए टैण्डर लगा दिए गए है। इनके बन जाने से गुरूग्राम में बरसाती पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद में बेहतर पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 12 रेनीवेल टयूबवैल लगाए जा रहे हैं जिनमें से आधे जून 2026 तक पूरे कर लिए जाएगें तथा शेष रेनीवेल टयूबवैल आगामी गर्मी के मौसम से पहले लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नांगल चैधरी में दिल्ली, मुम्बई, इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर पर सबसे ब?ा लोजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। इसी प्रकार हिसार में लोजिस्टिक हब का कार्य निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत?ी नरेला, मेरठ भिवानी ट्रांसमिशन लाईन तथा अमृतसर कटरा एक्सप्रैस वे का कार्य हरियाणा में पूरा हो चुका है। दिल्ली कटरा एक्सप्रैस वे का एक्सटेशन युवीआर नरेला दिल्ली से जो?ने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 78 फरीदाबाद तथा सेक्टर 9 गुरूग्राम में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए कामकाजी होस्टलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पानीपत, सोनीपत, रेवा?ी में भी कामकाजी महिला होस्टल बनाए जाएगें जिनके लिए प्रकिया जारी है। उन्होंने पंचकूला के कामकाजी होस्टल का जल्द ही संचालन किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डा. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ए के सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, आयुक्त एवं सचिव उद्योग एवं वाणिज्य डा. अमित अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव आबकारी एवं कराधान आशिमा बरा?ा, आयुक्त एवं सचिव मानव संसाधन पी सी मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा सरकार ने नाइटक्लब, बार और पब में प्रदेशव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए

मनदीप कौर

चंडीगढ़, हरियाणा सरकार ने नाइटक्लब, बार, पब और अन्य मनोरंजन स्थलों, जहाँ डांस फ्लोर होते हैं, का तत्काल अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश ऐसे प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा में हुई चूकों को देखते हुए जारी किए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ये आदेश सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की आग से संबंधित दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। डॉ. मिश्रा ने हरियाणा में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा मानकों के कड़े अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नाइटक्लब, बार, पब और इसी प्रकार के बड़े जनसमूह वाले प्रतिष्ठानों का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट तुरंत करवाएँ। ये ऑडिट राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 तथा हरियाणा अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार ही किए जाएंगे। अधिकारियों को सात दिन की समय–सीमा के भीतर इन ऑडिट को पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षणों में आपातकालीन निकास द्वारों की उपलब्धता और उनके सही ढंग से कार्य करने की स्थिति, आग बुझाने की व्यवस्थाओं की पर्याप्तता, लाइसेंस और अनुमतियों की वैधता तथा निर्धारित अग्नि और जीवन सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि ऑडिट के दौरान पाए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन या कमी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति नीति में किया बड़ा बदलाव

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

1984 दंगा प्रभावित परिवारों को मिलेगा रोजगार

चंडीगढ़, हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति, 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी नियमों में ॑परिवार॑ की मौजूदा परिभाषा के बावजूद, 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार का सर्वसम्मति से चिन्हित एक वर्तमान सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घटना हरियाणा में हुई या राज्य से बाहर। ऐसी नियुक्ति एचकेआरएन द्वारा निर्धारित लेवल–1, लेवल–2 अथवा लेवल–3 के तहत उपयुक्त पद पर, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाएगी। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि भविष्य में यदि उस विभाग में, जहां संबंधित अनुबंध कर्मचारी तैनात है, सभी पद भर जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को समान पदों की मांग (इंडेंट) प्राप्त होने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन एचकेआरएन द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से किया जाएगा। यदि किसी भी विभाग से ऐसी मांग उपलब्ध नहीं होती है, तो एचकेआरएन अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर कर्मचारी को समायोजित करेगा। यह संशोधन 30 जून, 2022, 26 अक्टूबर, 2023 तथा 13 मई, 2025 की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है तथा इसका उद्देश्य नीति के अनुकंपा और मानवीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करना है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप–मंडल अधिकारियों (नागरिक), विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और संशोधित नीति का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि बढ़ी

रमन कुमार

31 मार्च, 2026 तक बढ़ी अनुबंध अवधि

चंडीगढ़, 10 अक्टूबर–हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 31 मार्च, 2026 (4 माह) तक अथवा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाई गई थी। इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) द्वारा 25 मार्च, 2025 को जारी ज्ञापन में दी गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

एस. के. सक्सैना

बीएनएसएस–2023 के अनुरूप होगा अभियोजन विभाग का ढांचा

चंडीगढ़, 8 दिसंबर–हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, सक्षम और कानूनी रूप से सुदृढ़ अभियोजन संवर्ग के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

संसद द्वारा पारित नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप, बीएनएसएस–2023 में राज्य और जिला स्तर पर लोक अभियोजकों व अभियोजन निदेशालय से संबंधित कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार पहले ही 48 नए पदों को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें उप निदेशक के 24 और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं। ये पद बीएनएसएस–2023 की धारा 20 के तहत निदेशालय की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अनुभव निर्धारित करने के लिए अब ग्रुप–ए नियम 2013 में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के साथ हरियाणा अभियोजन विभाग अब एक अधिक मजबूत, कुशल और पूर्णत: अनुपालनीय ढांचे के साथ कार्य करने के लिए तैयार है, जिससे बीएनएसएस–2023 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी।

प्रदेश सरकार पहले ही 48 नए पदों को दे चुकी है मंजूरी, जिनमें उप निदेशक के 24 और सहायक निदेशक के 24 पद हैं शामिल

IISF पंचकूला में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल-भारत तेज़ी से 6G, एआई और नवाचार आधारित भविष्य की ओर अग्रसर

नए युग की प्रौद्योगिकियाँ – विज़न 2047' पर पैनल चर्चा में नई तकनीक को बढ़ावा देने का आह्वान

पंकज

चण्डीगढ़, – केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहरलाल ने पंचकूला में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (छ्ढ्ढस्न्र) के तीसरे दिन 'नए युग की प्रौद्योगिकियाँ – विज़न 2047' पर पैनल चर्चा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि नई तकनीक और नवाचार को आगे बढ़ाना और उन्हें समाज के हित में अधिक से अधिक लागू करना अब हमारे वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बन गई है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पंचकूला में हो रहा है और हम सभी इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा को फरीदाबाद में इस महोत्सव का आयोजन करने का अवसर मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इस फ़ेस्टिवल का उद्देश्य अकादमिक जगत और उद्योग जगत को एक मंच पर लाना है, ताकि दोनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान की ही बदौलत आज दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है। दूरसंचार के माध्यम से हम वायर और वायरलेस तकनीक का उपयोग कर एक–दूसरे से बात कर सकते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठे व्यक्ति को देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब इससे आगे बढ़ते हुए एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का दौर आ गया है, जिसे भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि एआई टूल्स का सही उपयोग करके किसी भी समस्या का प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है । उन्होंने कहा कि वे वैज्ञानिकों से अनुरोध करते हैं कि एआई का प्रयोग सावधानीपूर्वक और समाजहित में करें, ताकि इसका सार्थक रूप से अधिकतम लाभ उठाया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज एआई का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भी इसके प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। स्मार्ट मीटरिंग और आवश्यकता के अनुसार बिजली उपकरणों के संचालन में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे खर्च में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के अलावा आवासन के क्षेत्र में भी एआई का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकानों की डिजाइन इस प्रकार तैयार की जा सकती है कि वे सर्दियों में अत्यधिक ठंडे न हों और गर्मियों में बहुत गर्म न हों। इसमें एआई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। श्री मनोहर लाल ने कहा की भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ का अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष शुरू किया, जो एआई, क्वांटम, स्वच्छ ऊर्जा और बायोटेक जैसे रणनीतिक और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के तहत पेशेवर निधि प्रबंधकों के माध्यम से संचालित, गहन तकनीक परियोजनाओं को वित्तपोषित करके और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत अब संचार तकनीक में 5ल से आगे बढ़कर तेज़ी से 6ल की ओर अग्रसर हो रहा है। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल ने विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। हरियाणा से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हरियाणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और अनुसंधान को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री मोहनलाल ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी नारायण, आईआईटीएम के निदेशक डॉ. सूर्यचंद्र राव, सीएसआईआर–सीएसआईओ के निदेशक डॉ. शांतनु भट्टाचार्य सहित अन्य पैनलिस्ट भी उपस्थित थे।

कुरुक्षेत्र श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा में देवमाली पुस्तक का महंत महेश मुनि ने किया विमोचन

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

कुरुक्षेत्र, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक 7 दिसंबर ॰ पुस्तक का विमोचन कुरुक्षेत्र स्थित श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के महंत महेश मुनि जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। उक्त पुस्तक श्री देवनारायण जी द्वारा की गई पूजा स्थल देवमाली गांव के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संदर्भ को ध्यान में रखकर लिखी गई है। देवमाली एक ऐसा स्थान है जो देव कृपा से अभिभूत है। यह गांव पूरी तरह से सात्विक है तथा एक ही परिवार के सभी लोग यहां रहते हैं। आज की 21वीं सदी में भी यह गांव सतयुग की याद दिलाता है। यहां सभी मकान कच्चे हैं तथा लोग घरों में ताला नहीं लगाते। यहां पर श्री देव जी की कृपा बरसती है तथा लोग बहुत ही शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज तक यहां चोरी डकैती का कोई मामला दर्ज नहीं है। यहां कोई भी व्यक्ति दुर्व्यसन नहीं करता। यह सभी देव कृपा से ही संभव है। इससे पहले भी लेखक विष्णु अवतार श्री देवनारायण जी पर व देव जी की फड़ कथा पर दो पुस्तक लिख चुके हैं। यह दोनों पुस्तकें इंडिया बुक ऑफ रिकॉड्र्स में भी दर्ज हैं। इस अवसर पर सरदार मनजीत सिंह खैरा, महंत मंगल मुनी, महंत देवी शरण, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक, शिवम चौधरी, रमणीत सिंह, सानवी व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने लेखकों को शुभाशीष व आशीर्वाद दिया कि वे निरंतर इसी प्रकार अपना लेखन कार्य रखें। क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भी लेखकों को बधाई प्रेषित की है। इस पुस्तक के लोकार्पण से देव भक्तों में हर्ष व्याप्त है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म कर कार्यस्थल पर लौटने की करी अपील

मनदीप कौर

डॉक्टरों की लगभग सभी मांगें सरकार ने मानी

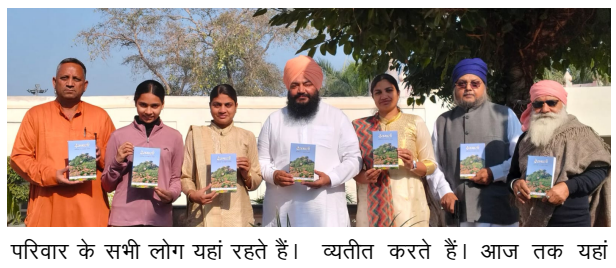

चंडीगढ़, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे अपनी हड़ताल वापस लेकर तुरंत अपने–अपने कार्यस्थलों पर लौट आएँ ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री आज यहां किसानों को मुआवजा राशि जारी करने उपरान्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की मुख्यत: चार मांगें थीं, जिनमें से तीन मांगें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के स्पेशलाइज्ड कैडर के गठन की मांग पर वित्त विभाग 16 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर चुका है।इसी प्रकार, हॉस्पिटल ड्यूटी से बाहर जाने पर यात्रा भत्ता प्रदान करने संबंधी मांग पर भी 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी हो चुकी है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती न करने की मांग पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने तक प्रदेश में एसएमओ की सीधी भर्ती स्थगित रहेगी। उनकी चौथी मांग, एसीपी संरचना में बदलाव, फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लगातार सुधार हुआ है और प्रदेश के लोगों का रुझान भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ा है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों को बधाई भी दी।

श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली तक विशेष ट्रेन का संचालन

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

जम्मू, जम्मू मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए समय समय पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाता हैं। जिससे की रेलवे द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ, अतिरिक्त भीड प्रबंधन के दौरान यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाया जा सके। इसी के तहत यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए , नई दिल्ली – श्री माता वैष्णो देवी कटरा – नई दिल्ली तक दिनांक 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक विशेष ट्रेन संख्या 04081/ 04082 चलाने का निर्णय लिया गया हैं।

विशेष ट्रेन का विवरण

विशेष ट्रेन संख्या 04081 नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिनांक 12.12.25 से 13.12.25 (दो ट्रिप)

यह विशेष ट्रेन दिनांक 12 दिसंबर को नई दिल्ली से रात 11.45 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर में 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन पानीपत, कुरूक्षेत्र, अम्बाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू , शहीद कैप्टन तुषार महाजन (उधमपुर) आदि रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी।

विशेष ट्रेन संख्या 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली दिनांक 13.12.25 से 14.12.25 (दो ट्रिप)

यह विशेष ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से रात को 09.20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन शहीद कैप्टन तुषार महाजन (उधमपुर) , जम्मू, पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लुधियाना, अम्बाला कैंट, कुरूक्षेत्र,पानीपत आदि रेलवे स्टेशनों पर यथावत रूकेगी।

जम्मू मंडल में समय–समय पर चलने वाली विशेष ट्रेन पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री उचित सिंघल ने बताया, 卐 कि यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा विकल्प प्रदान करते हुए, इस विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा हैं। साथ ही इस विशेष ट्रेन के चलने से यात्रियों को भीड़ भाड़ के दौरान कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। यह आरक्षित विशेष ट्रेन है, जिसका संचालन 20 कोचों के साथ किया जाएगा। यात्री भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट/ एप या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं, तथा यात्रियों से अनुरोध किया जाता है, कि अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले ट्रेन के समय की सटीक जानकारी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार दिवस समारोह में शामिल हुईं

रमन कुमार

नई दिल्ली, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार दिवस समारोह में शामिल हुईं और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकार दिवस हमें यह याद दिलाता है कि सर्व–जन मानवाधिकार अलग नहीं किए जा सकते हैं और वे एक न्यायपूर्ण, समतावादी और करुणामय समाज की आधारशिला हैं। सतहत्तर वर्ष पहले, विश्व एक सरल लेकिन क्रांतिकारी सत्य को व्यक्त करने के लिए एकजुट हुआ था कि प्रत्येक मनुष्य गरिमा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान पैदा होता है। मानवाधिकारों के वैश्विक ढांचे को आकार देने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मानवीय गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित विश्व की कल्पना की थी।

सर्व–जन मानवाधिकार अलग नहीं किए जा सकते और वे एक न्यायपूर्ण, समतावादी और करुणामय समाज की आधारशिला हैं–राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

मुख्यमंत्री ने की जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की बजट घोषणाओं और सीएम घोषणाओं की समीक्षा

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ तुरंत और प्रभावी रूप से उपलब्ध करवाना है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ कार्य करें। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि महाग्राम योजना के तहत 12 चयनित गांवों में शहरी स्तर की पेयजल एवं सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। अब तक भोरा कलां (गुरुग्राम), भैंसवाल कलां (सोनीपत) और खाम्बी (पलवल) में पेयजल व सीवरेज नेटवर्क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दो अन्य गांवों में शेष कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज होगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि विभिन्न शहरों में 150 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने की बजट घोषणा के तहत 23 शहरों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 100 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य भी अगले तीन महीनों में पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा दक्षिण कोरिया के व्यापारिक दिग्गज़ों से विचार-विमर्श

पैंग्यो टेक्नो वैली की तर्ज़ पर मोहाली को विकसित करने की घोषणा

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दक्षिण कोरिया की अग्रणी कंपनियों– डैवू इंजीनियरिंग एवं निर्माण, जी.एस. इंजीनियरिंग एवं निर्माण, नॉन्गशिम, कोरिया रक्षा उद्योग संघ, सियोल व्यवसाय एजेंसी तथा अन्य अनेक कंपनियों–को राज्य में निवेश करने का आमंत्रण दिया। दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने डैवू इंजीनियरिंग एवं निर्माण के चेयरमैन जंग वॉन जू से मुलाक़ात की और नवोन्मेषी ऊर्जा परियोजनाओं–समुद्री पवन ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन–में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढाँचे–तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल, पेट्रो–रासायनिक परिसर, उर्वरक संयंत्र–तथा आधुनिक आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं, स्मार्ट नगर परियोजनाओं, और सड़क, पुल, रेल, बंदरगाह व हवाई अड्डों से संबंधित सिविल ढाँचे में सहयोग की अपार संभावनाएँ हैं।

मुख्यमंत्री ने मॉड्यूलर तथा पूर्व–निर्मित ढाँचों की आधुनिक निर्माण तकनीक में तकनीकी आदान–प्रदान की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि तेज़ और किफायती निर्माण मॉडल विकसित किए जा सकें।

डैवू इंजीनियरिंग एवं निर्माण जैसी विश्वविख्यात अवसंरचना कंपनी के साथ रणनीतिक बैठक के दौरान उन्होंने पंजाब की मजबूत औद्योगिक गति, आधुनिक बुनियादी ढाँचों के निर्माण हेतु चल रहे प्रमुख प्रयासों तथा निवेश पंजाब प्रणाली के अंतर्गत विशेष संयुक्त निरीक्षण ढाँचे की जानकारी साझा की। उन्होंने वैश्विक उद्योग समूह को पंजाब में व्यापक आधारभूत विकास, आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रस्तावित औद्योगिक नगरों में संभावनाओं की खोज करने हेतु प्रोत्साहित किया।

उन्होंने पर्यावरण–अनुकूलता के वैश्विक मानकों के अनुरूप चलने वाली पहलों–ईएसजी प्रतिबद्धताओं और हरित हाइड्रोजन कार्यक्रमों–में साझा प्रयासों पर भी ज़ोर दिया।

प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की वकालत, गोलमेज़ सम्मेलन में पंजाब को सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल बताया

इसके बाद हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने जी.एस. इंजीनियरिंग एवं निर्माण के वाइस चेयरमैन यंग हा युं से मुलाक़ात की। उन्होंने सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसी नव्य ऊर्जा परियोजनाओं; सड़क, पुल और स्मार्ट नगर जैसी आधारभूत परियोजनाओं; तथा औद्योगिक परिसरों एवं अभिकल्प–खरीद–निर्माण (ई.पी.सी.) सेवाओं के क्षेत्र में समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने मॉड्यूलर निर्माण तकनीक और हरित हाइड्रोजन तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशाल संभावनाओं का उल्लेख किया और राज्य सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया।

नॉन्गशिम होल्डिंग्स के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में संयुक्त कार्य का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारतीय स्वादानुसार नवीन त्वरित–पकवान (इंस्टैंट) नूडल्स के नए संस्करण विकसित करने की आवश्यकता बताई, साथ ही भारत की सुपरमार्केट श्रृंखलाओं और ई–वाणिज्य मंचों पर इनके वितरण के विस्तार पर भी चर्चा की।

उन्होंने युवा वर्ग और स्वास्थ्य–सचेत उपभोक्ताओं तक ब्रांड की पहुँच बढ़ाने, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ पर्यावरण–हितैषी पैकेजिंग समाधान विकसित करने तथा दीर्घकालिक उपयोग योग्य खाद्य पदार्थ और पौध–आधारित विकल्पों पर अनुसंधान में साझेदारी की वकालत की।

कोरिया रक्षा उद्योग संघ (के डी आई ए) के वाइस चेयरमैन ली सुंग क्यू से बातचीत में मुख्यमंत्री ने रक्षा निर्माण, रक्षा–तकनीक के आदान–प्रदान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और मानव–रहित प्रणालियों जैसी उन्नत सैन्य तकनीकों में सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की।

उन्होंने सायबर सुरक्षा तथा कौशल–विकास कार्यक्रमों में साझा प्रयास करके रक्षा निर्माण क्षेत्र में दक्ष जनशक्ति तैयार करने की संभावनाओं पर भी बल दिया।

सियोल व्यवसाय एजेंसी के स्टार्टअप प्रभाग के निदेशक जोंग वू किम के साथ मुलाक़ात के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब–आधारित नवोन्मेषी उद्यमों को वैश्विक बाज़ार तक पहुँचाने हेतु उनके त्वरक (एक्सलेरेशन) और इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

उन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी–तंत्र, अनुसंधान–विकास, नवाचार–संस्कृति तथा उत्पाद–प्रमाणीकरण (जैसे सियोल पुरस्कार) में साझेदारी को समय की आवश्यकता बताया।

इसके बाद आयोजित पंजाब में व्यवसाय सुगमता पर गोलमेज़ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया की अग्रणी वाणिज्यिक, निवेश और उद्योग कंपनियों–बी.के.एल., यूलचोन, बडट्री प्रबंधन समूह, एस.के. प्रतिभूति, किम एंड चांग, शिन एंड किम, ली एंड को, डेन्टन्स ली, कोरिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, कोरिया रोबोट उद्योग संघ, कोरिया व्यापार–निवेश प्रोत्साहन संगठन, कोरिया ऑटो–भाग उद्योग सहकारी, युआन्टा प्रतिभूति, कैपस्टोन परिसंपत्ति प्रबंधन, एन.एच. निवेश एवं प्रतिभूति, और कोरिया औद्योगिक अर्थशास्त्र एवं व्यापार संस्थान–के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने पंजाब को सर्वाधिक उपयुक्त निवेश स्थान बताते हुए राज्य सरकार द्वारा की गई प्रमुख सुधार पहलों से इन्हें अवगत कराया और उद्योग विकास को और सहज बनाने हेतु सुझाव भी मांगे।

आई.एन.एस. कोच्चि मॉडल के उद्घाटन के साथ एम.आर. एस.ए.एफ.पी.आई. में ट्राइ-सर्विसेज मिलिट्री हेरिटेज डिस्प्ले हुआ पूर्ण

नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आई.एन.एस. कोच्चि के स्केल–डाउन मॉडल का किया उद्घाटन

पंकज

चंडीगढ़, ट्राई–सर्विसेज मिलिट्री डिस्प्ले के समापन समारोह को दर्शाते ऐतिहासिक कार्यक्रम में, भारतीय नौसेना के प्रमुख कोलकाता–क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आई.एन.एस. कोच्चि (डी64) के स्केल–डाउन मॉडल का उद्घाटन महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई.) में किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना दिवस–2025 पर प्रस्तुत किए गए इस मॉडल का उद्घाटन वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ए.वी.एस.एम., एन.एम., वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ द्वारा किया गया। इस जहाज मॉडल की स्थापना के साथ एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. परिसर अब तीनों सैन्य सेवाओं के प्रमुख उपकरणों का केंद्र बन गया है, जिससे युवा कैडेटों को प्रेरणा देने के लिए एक समग्र और अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा। संस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास यह भी है कि इसके 22 पूर्व कैडेट भारतीय नौसेना में कमीशंड अधिकारी के रूप में सेवाएँ दे रहे हैं, जिनमें से दो कैडेट हाल ही में एजिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। एम.आर.एस. ए.एफ.पी.आई. के कैडेटों और शेमरॉक सीनियर सेकंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने पंजाब की समुद्री विरासत का उल्लेख करते हुए पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह का उदाहरण देते हुए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा, समुद्री हितों की सुरक्षा और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन से हुई बातचीत और वास्तविक सैन्य उपकरणों के बारे में मिली महत्वपूर्ण जानकारी कैडेटों में नेतृत्व, टीमवर्क और समस्या–समाधान जैसे आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायक होगी। यह कार्यक्रम कैडेटों में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा की भावना को भी मजबूत करेगा, जो उन्हें रक्षा सेवाओं सहित चुनौतीपूर्ण करियर के लिए तैयार करेगा। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उन युवाओं को पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है जो सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना देखते हैं और उनके लिए आवश्यक संसाधन व अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

वास्तविक सैन्य उपकरणों से रूबरू होकर कैडेटों में नेतृत्व और टीमवर्क की भावना का होगा विकास –अमन अरोड़ा

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने ऑब्ज़र्वेशन होम और अलग-अलग गांवों में नशे के खिलाफ़ किए जागरूकता प्रोग्राम

मनदीप कौर

होशियारपुर, –जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर ने पंजाब स्टेट कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एस. ए. एस नगर के दिशा निर्देशों और जिला एवं सेशंस जज होशियारपुर राजिंदर अग्रवाल के आदेशों पर, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर के सेक्रेटरी नीरज गोयल ने आज ऑब्ज़र्वेशन होम, राम कॉलोनी कैंप, होशियारपुर और अलग–अलग गांवों में जागरूकता प्रोग्राम किए, जिनका मकसद युवाओं को ड्रग्स न लेने के बारे में जागरूक करना था। इस मौके पर अवेयरनेस सेमिनार की अध्यक्षता विक्रम सिंह बार वाइस प्रेसिडेंट, आशीष ज्योति पैनल एडवोकेट, तरुणवीर पैनल एडवोकेट, विंसी मलिक पैनल एडवोकेट, दलवीर सिंह पैनल एडवोकेट, हरकीरत सिंह एडवोकेट, सरिता कंवर रिटेनर एडवोकेट, बरजिंदर सिंह पैनल एडवोकेट, विवेक कंवर बार प्रेसिडेंट, हरजिंदर कुमार वर्मा डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल और करण लूथरा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल होशियारपुर ने की। सेमिनार के दौरान युवाओं और कम्युनिटी को इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस का मुख्य मकसद युवा पीढ़ी को भविष्य में नशा छोड़ने और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि नशा इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और घर में अशांति पैदा करता है। नालसा (ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन – फॉर ड्रग फ्री इंडिया), प्लान 2025 और सेहत, परिवार और सामाजिक जीवन पर ड्रग्स के असर और एन.डी.पी.एस एक्ट के कानूनी नियमों के बारे में जानकारी दी गई। आखिर में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, होशियारपुर में काम कर रहे पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा जागरूकता मटीरियल बांटा गया। इसके अलावा, सेक्रेटरी नीरज गोयल की अगुवाई में आज सुश्री रेणु पैनल एडवोकेट होशियारपुर ने तीसरे सेशन में नए भर्ती हुए पैरा लीगल वॉलंटियर्स को रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग दी।

AI विकसित भारत 2047 की यात्रा में देगा महत्वपूर्ण योगदान- IISF 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

केंद्रीय मंत्री ने IISF 2025 में भारत की बढ़ती तकनीकी नेतृत्व क्षमता को किया रेखांकित

मनदीप कौर

पंचकुला, माननीय केंद्रीय मंत्री (विद्युत मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) श्री मनोहर लाल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विकसित भारत 2047 की यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। विकास के लिए AI: एक रूपांतरकारी लेकिन संवेदनशील तकनीक श्री मनोहर लाल ने कहा कि ‹द्ध के माध्यम से भविष्य में नवाचार, स्टार्टअप और कौशल विकास इत्यादि को मिलेगी, लेकिन इसका जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि "AI अच्छा सर्वेंट है लेकिन बैड मास्टर। उन्होंने समस्या समाधान, डेटा विश्लेषण, जेनेटिक्स, ऊर्जा प्रबंधन और आवास तकनीकों में ‹द्ध की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उभरती तकनीकें नए रोजगार पैदा करेंगी और माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक उत्पादकता बढ़ाएंगी।

भारत की वैज्ञानिक यात्रा का उत्सव

केंद्रीय मंत्री ने बचपन के विज्ञान प्रदर्शनों की अपनी व्यक्तिगत यादें साझा कीं और कहा कि जिज्ञासा–आधारित प्रयोग अक्सर बड़े आविष्कारों की नींव बनते हैं। उन्होंने सर आइज़क न्यूटन और ग्रामीण नवप्रवर्तक धर्मवीर कांबोज़ की यात्राओं का उल्लेख करते हुए सवाल पूछने की शक्ति को उजागर किया। श्री मनोहर लाल ने भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राचीन दूरसंचार के सिद्धांतों से लेकर चंद्रयान मिशनों और डिजिटल तकनीकों तक, जिन्होंने दुनिया को हमारी हथेली में समेट दिया है।

मंत्री महोदय ने अपने मंत्रालयों में AI–आधारित पहलों का उल्लेख किया, जिनमें स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा–कुशल प्रणालियाँ और जलवायु–अनुकूल आवास डिज़ाइन शामिल हैं। उन्होंने नई तकनीकों के प्रति जनता में विश्वास, पारदर्शिता और जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान भारती, भाग लेने वाले संस्थानों और सभी आयोजकों को IISF 2025 की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने उद्योग, अकादमिक जगत, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप और छात्रों के बीच सहयोग की सराहना की और कहा कि ऐसी साझेदारी भारत को वैज्ञानिक नवाचार में अग्रणी बनाने में मदद करेगी।

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का प्रदर्शन–अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने हाल की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 57 भारतीय उपग्रह लगभग 50 अनुप्रयोगों का समर्थन कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या तीन गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने AI–सक्षम प्रणालियों, नई प्रोपल्शन तकनीकों और अगली पीढ़ी के पेलोड्स में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि आदित्य–1 शानदार प्रदर्शन कर रहा है। 63 वर्षों की भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं को दर्शाता हुआ नौ मिनट का विशेष वीडियो भी साँझा किया।

पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही पंचकूला में की जाएगी

पंकज

चंडीगढ़, – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विष्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। 'पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामत: कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 08,17, 22 और 29 दिसम्बर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छः महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

अपने देश के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनें और कोरियन कंपनियों को पंजाब में निवेश के लिए प्रेरित करें-सियोल के पंजाबियों से मुख्यमंत्री की अपील

जापान की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद भगवंत मान ने अपनी दक्षिण कोरिया यात्रा की शुरुआत की

मनदीप कौर

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज सियोल में रह रहे प्रवासी पंजाबियों को प्रदेश के राजदूत बनकर काम करने का आह्वान किया, ताकि कोरियन कंपनियों को पंजाब, जो अब विश्व भर में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है, में निवेश के लिए प्रेरित किया जा सके। दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान सियोल में पंजाबी समुदाय के साथ विचार–विमर्श कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की उद्योग–हितैषी नीतियों के कारण निवेशक पहले से ही पंजाब में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं और सियोल के पंजाबियों को प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनकर निवेश आकर्षित करने में और मदद करनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबी जन्मजात उद्यमी हैं और हममें से हर एक को प्रदेश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। पंजाबियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव दिखाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले से ही प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है और अब अपनी जन्मभूमि की सेवा करने की बारी प्रवासी पंजाबियों की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास को बड़ा बल मिलेगा, जिससे रंगला पंजाब बनेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाबी वैश्विक नागरिक हैं, जिन्होंने दुनिया के हर कोने में अपना अलग मुकाम बनाया है और कड़ी मेहनत का जजज्बा पंजाबियों के खून में बसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने पंजाबी समुदाय की उद्यमशीलता, सांस्कृतिक प्रतिबद्धता तथा लोगों–से–लोगों और कारोबार–से–कारोबार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कोरियन कंपनियों का मार्गदर्शन करते हुए पंजाब को प्राथमिक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने में सक्रिय भूमिका निभाने की भी अपील की। भगवंत सिंह मान ने रोजगार, नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए और अधिक अवसर पैदा करने में मदद के लिए उनसे समर्थन और सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका विजन बिल्कुल स्पष्ट है – नीतिगत स्थिरता, तेज निर्णय प्रक्रिया और निवेशकों के समय एवं विश्वास का सम्मान करने वाली शासन व्यवस्था देकर पंजाब को वैश्विक उद्योग के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब का दृष्टिकोण साझेदारी और उद्योगों के साथ मिलकर काम करने, उनकी जरूरतों को समझते हुए यह सुनिश्चित करने पर आधारित है कि सरकार विकास की साझेदार बने। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पंजाब ने अपना आधारभूत ढांचा मजबूत किया है, औद्योगिक क्षमता का विस्तार किया है और निवेश के नए रास्ते खोले हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शासन एवं नियामक सुधारों का भी जिक्र किया, जिनमें फास्टट्रैक पंजाब सिंगल–विंडो सिस्टम, 173 सेवाओं की ऑटो–डीम्ड मंजूरी, पैन–आधारित कारोबारी पहचान और पंजाब कारोबार अधिकार अधिनियम में संशोधन शामिल हैं, जो समयबद्ध सैद्धांतिक मंजूरियां सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने पंजाब के औद्योगिक आधारभूत ढांचे पर भी प्रकाश डाला और बताया कि 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पहले ही इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से सुनिश्चित किया जा चुका है। इस दौरान भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि उनका दृष्टिकोण सरल और स्पष्ट है, नीतिगत स्थिरता, निर्णय में गति और निवेशकों के समय एवं विश्वास का सम्मान करने वाली शासन व्यवस्था देकर पंजाब को विश्व उद्योग के लिए पसंदीदा स्थान बनाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की सोच साझेदारी और उद्योगों के साथ मिलकर काम करने पर आधारित है ताकि उद्योगों की जरूरतों को समझते हुए सरकार विकास की दिशा में सकारात्मक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने अपना आधारभूत ढांचा मजबूत किया है, औद्योगिक क्षमता बढ़ाई है और निवेश के नए मार्ग खोले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग जगत के बीच साझेदारी ही सफलता की कुंजी है और प्रदेश सरकार का दृढ़ विश्वास है कि औद्योगिक विकास तभी संभव है जब हम बराबर के साझेदार के रूप में काम करें। इस दौरान प्रवासी समुदाय ने मुख्यमंत्री के दल का गर्मजोशी भरा स्वागत किया। उन्होंने पंजाब की वैश्विक पहुंच तथा त्योहारों, भाषा, व्यंजनों और रीति–रिवाजों के उत्सवों के माध्यम से कोरियाई लोगों में पंजाबी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। प्रवासी समुदाय ने उम्मीद जताई कि यह दौरा पंजाब–दक्षिण कोरिया संबंधों में नया अध्याय शुरू करेगा, जिससे उद्योग, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान–प्रदान में दीर्घकालिक साझेदारी और रचनात्मक परिणामों का मार्ग प्रशस्त होगा।

पंजाब को दुनिया के सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रवासी पंजाबियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया

काशी तमिल संगमम् के अंतर्गत पुलिसकर्मी और नमो घाट पर रहने वाले परिवार सीख रहे हैं तमिल

रमन कुमार

नई दिल्ली–काशी तमिल संगमम् 4.0 का इस वर्ष का मुख्य विषय ₭तमिल सीखें – तमिल करकलाम₭ है, जिसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषाई और सांस्कृतिक सेतु को और अधिक सशक्त बनाना है। इसी थीम के अंतर्गत वाराणसी में एक प्रेरणादायक और मन को छू लेने वाली पहल देखने को मिली। एक ओर, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने तमिल भाषा का प्रशिक्षण लिया ताकि काशी आने वाले तमिलभाषी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सहायता वे और भी सहज तथा प्रभावी ढंग से कर सकें। उन्हें दैनिक संवाद, अभिवादन तथा यात्रियों से सामान्य बातचीत के लिए आवश्यक तमिल वाक्य सिखाए गए।

ऑपरेशन सागर बंधु - भारतीय नौसेना ने श्रीलंका को 1000 टन मानवीय सहायता सामग्री और आपदा राहत सामग्री पहुंचाने के लिए चार और युद्धपोत भेजे

मनदीप कौर

नई दिल्ली–श्रीलंका को तत्काल खोज एवं बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय नौसेना ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को (एचएडीआर) सामग्री की आपूर्ति हेतु चार और जहाज– आईएनएस घड़ियाल, एलसीयू 54, एलसीयू 51 और एलसीयू 57 तैनात किए हैं। इससे पहले आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस सुकन्या ने राहत सहायता तथा हेलीबोर्न एसएआर सहायता प्रदान की हैं। ये तीन एलसीयू (लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी) 7 दिसंबर, 2025 की सुबह कोलंबो पहुंचे और श्रीलंका के अधिकारियों को महत्वपूर्ण राहत सामग्री सौंप दी। मानवीय सहायता मिशन जारी रखने के लिए आईएनएस घड़ियाल 8 दिसंबर, 2025 को त्रिंकोमाली पहुंच गया है।

संरक्षा, दायित्व और जन विश्वास - नए अधिनियम से क्या हासिल होगा

लेखक
डा. रतन कुमार सिन्हा
पूर्व सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
एवं पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग

जनता का विश्वास हमेशा से भारत के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रहा है। देश के सतत, समतापूर्ण और ऊर्जा–सुरक्षित विकास के दृष्टिकोण में यह आधार निहित है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग अत्यधिक संरक्षा, निर्विवाद उत्तरदायित्व और पारदर्शी संचार के साथ किया जाए। संरक्षा, दायित्व और जन विश्वास के स्तंभ केवल अमूर्त आदर्श नहीं हैं; ये भारत के परमाणु उद्योग के व्यावहारिक आधार हैं।

जैसे–जैसे हम परमाणु ऊर्जा के लिए एक नए विधायी ढाँचे पर विचार कर रहे हैं, यह पूछना ज़रूरी है कि यह नए अधिनियम से क्या हासिल होगा? मेरे विचार से, इसका उत्तर इन्हीं आधारों को मज़बूत करने में निहित है। इस कानून से अपेक्षा है कि यह जनता के विश्वास से समझौता किए बिना संरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करे, सरलीकरण और सुरक्षा प्रदान करे, नवाचार को प्रोत्साहित करे।

संरक्षा – पूर्णता की संस्कृति को संस्थागत बनाना

परमाणु प्रौद्योगिकी में संरक्षा डिज़ाइन का एक अनिवार्य अंग ही नहीं, बल्कि यह इसका मूल दर्शन होना चाहिए। ट्रॉम्बे में भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टरों से लेकर स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टरों और अगली पीढ़ी के प्रगत रिएक्टरों तक, डिज़ाइन हमेशा गहन संरक्षा और निश्चेष्ट संरक्षा विशेषताओं द्वारा निर्देशित रही हैं।

जब हमने प्रगत भारी पानी रिएक्टर (AHWR) की कल्पना की थी, तो हमारा लक्ष्य न केवल थोरियम के उपयोग को प्रदर्शित करना था, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना था कि एक रिएक्टर इसके ऑपरेटर के हस्तक्षेप के बिना भी सुरक्षित रह सकता है – एक ऐसी डिजाइन जो स्वत- सुरक्षित (walk-away safe) हो। वास्तव में, संरक्षा परमाणु ऊर्जा परिनियोजन का एक अभिन्न अंग है।

नए अधिनियम को, निश्चित रूप से, यह गारंटी देनी चाहिए कि संरक्षा–संस?कृति जारी रहे। इसे उच्चतम संरक्षा मानकों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए और नियामक संस्थानों की स्वायत्तता, अधिकार और जवाबदेही को मजबूत करना चाहिए। इसे आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन और पारदर्शी संरक्षा समीक्षाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसे प्रचालन प्रदर्शन पर सूचना के आदान–प्रदान को भी बढ़ावा देना चाहिए।

किसी भी उद्योग में विशेषकर परमाणु ऊर्जा के मामले में तो और भी ज़्यादा, संरक्षा एक स्थिर लक्ष्य नहीं है। इसे एक ऐसी संस्कृति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका निरंतर पोषण किया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में, इस संस्कृति को एक संस्थागत फेमवर्क के ज़रिए मज़बूत किया जाना चाहिए।

दायित्व – स्पष्टता के साथ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना

नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी अधिनियम) एक अग्रणी कदम रहा है जिसने तीन महत्वपूर्ण हितों को संतुलित किया है- जनता की संरक्षा, आपूर्तिकर्ताओं को आश्वासन और ऑपरेटरों का विश्वास। इसने दोष–रहित दायित्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया और यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी स्पष्ट और निर्देशित रहे।

ऊर्जा परिदृश्य और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास ने संबंधित संस्थाओं की देनदारियों पर अधिक स्पष्टता को आवश्यक बना दिया है। इस तरह के संशोधन किसी भी परिपक्व क्षेत्र की स्वाभाविक प्रगति का हिस्सा हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन का फेमवर्क वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखे।

नए अधिनियम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन का फेमवर्क निष्पक्ष, स्पष्ट हो और संदेह रहित बना रहे, साथ ही जवाबदेही की एक सुपरिभाषित श्रृंखला भी बनाए रखे। इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दायित्व का मूल्यांकन करने की व्यवस्था देश में परमाणु तैनाती की सीमा और पैमाने के अनुरूप हो। एक आधुनिक दायित्व व्यवस्था को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि संरक्षा और ज़िम्मेदारी विकास के साथ–साथ चलती हैं।

जन विश्वास – प्रगति की आधारशिला

दुनिया भर में परमाणु उद्योग के उत्कृष्ट संरक्षा रिकॉर्ड के बावजूद, परमाणु ऊर्जा के प्रति जनता का दृष्टिकोण अक्सर वैज्ञानिक तथ्यों की तुलना में धारणाओं से अधिक प्रभावित होता रहा है। कुछ साल पहले मैंने जिस पुस्तक का सह–लेखन किया था, द अनरीज़न्ड फियर ऑफ़ रेडिएशन, ऐसी ही भ्रांतियों को दूर करने का एक प्रयास था। यह पुस्तक बताती है कि नियंत्रित और सुव्यवस्थित वातावरण में विकिरण, किसी भी अन्य तकनीक जितना ही सुरक्षित है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से आत्मविश्वास से करते हैं।

जनता का विश्वास केवल पारदर्शिता और जनता के साथ संवाद के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब नागरिक देखते हैं कि परमाणु विज्ञान रेडियोथेरेपी के माध्यम से जीवन बचा रहा है, उत्परिवर्तन प्रजनन के माध्यम से फसलों को बढ़ा रहा है या विकिरण शुद्धिकरण के माध्यम से सुरक्षित जल उपलब्ध करा रहा है, तो वे परमाणु ऊर्जा के मानवीय पहलू से जुड़ने लगते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, हमने नई आउटरीच रणनीतियों की शुरुआत करके इस दिशा में कई प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप 2015 की गणतंत्र दिवस परेड में परमाणु ऊर्जा विभाग की झांकी प्रदर्शित की गई और प्रसारण व सोशल मीडिया पर उपस्थिति दर्ज कराई गई। ये कदम दिखावटी नहीं थे; इनका उद्देश्य विज्ञान और समाज के बीच की दीवार को हटाना था।

यदि नया अधिनियम नागरिकों के साथ खुले संवाद को बढ़ावा दे पाता है, तो यह समाज के साथ विज्ञान के सामाजिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करेगा। ऐसा करके, यह हमारे चिरस्थायी आदर्श वाक्य- राष्ट्र की सेवा में परमाणु, की भावना को साकार करेगा।

नए अधिनियम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के संदेश सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाएं, शैक्षिक जागरूकता को प्रोत्साहित करें तथा नागरिकों के साथ संवाद को संस्थागत कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाएं।

नए अधिनियम में क्या गारंटी होनी चाहिए

यदि 1962 के प्रथम परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने क्षमता निर्माण के मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो नए अधिनियम का उद्देश्य आत?मविश?वास बढ़ाना और परमाणु प्रौद्योगिकी की बड़े पैमाने पर तैनाती करना होना चाहिए। इसमें उस राष्ट्र की परिपक्वता प्रतिबिंबित होनी चाहिए जिसने जटिल तकनीकों में महारत हासिल की है और जिम्मेदार आचरण के माध्यम से वैश्विक सम्मान अर्जित किया है। नए अधिनियम को विज्ञान और समाज के बीच पारस्परिक आश्वासन की यह गारंटी देनी चाहिए कि-

संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, दायित्व (देनदारियां) हमेशा न्यायसंगत और पारदर्शी रहेगा, और जनता का विश्वास हर निर्णय के केंद्र में रहेगा।

जब ये गारंटियां न केवल कानून में, बल्कि संस्थागत व्यवहार में भी निहित होंगी, तो भारत का परमाणु भविष्य सुदृढ़ आधार पर खड़ा होगा।

विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए यह एक परिवर्तन का दौर है। बड़े विद्युत संयंत्रों के अलावा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और प्रगत थोरियम प्रणालियाँ परमाणु ऊर्जा की पहुँच का विस्तार करेंगी। इसलिए नए अधिनियम को एक ऐसे फेमवर्क की गारंटी देनी चाहिए जो प्रौद्योगिकियों के तेज़ उपयोग को सुगम बनाए और साथ ही स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करे। इसमें नियामकों, प्रचालकों और उद्योग के बीच निर्बाध समन्वय और भविष्य के नवाचारों को शामिल करने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना चाहिए।

संक्षेप में, नए अधिनियम को परमाणु पुनर्जागरण के लिए एक अनुकूल पृष्?ठभूमि तैयार करनी चाहिए जो भारत में जलवायु लक्ष्?यों और विकसित भारत ‡2047 बनने की राह में स्?वच?छ–ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को विश्?व का अग्रणी देश बनने की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना, इस सदन में हम सब का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त, इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बना रहे हैं। एक ऐसा कालखंड, जो हमारे सामने इतिहास के अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। यह चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी ही, लेकिन आने वाली पीढियां के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी यह शिक्षा का कारण बन सकती है, अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यह एक ऐसा कालखंड है, जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय फिर से हमारे सामने उजागर हुए हैं। अभी–अभी हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्व मनाए हैं। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहा है और अभी–अभी हमने गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस भी बनाया है और आज हम वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यह यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है।

लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी,

वंदे मातरम को जब 50 वर्ष हुए, तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने–मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए, तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के (अस्पष्ट) गिरोह में थे।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं, सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है, जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावनात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं। यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं, एक्चुअली हमारे लिए ऋण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्ष्यावादी लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के ऋण स्वीकार करने का यह पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोलकर आगे बढ़ा, फिर से एक बार अवसर है कि आओ, हम सब मिलकर चलें, देश को साथ लेकर चलें, आजादी का दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम 150 हम सब की प्रेरणा बने, हम सब की ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने, 2047 में विकसित भारत बनाकर के हम रहें, इस संकल्प को दोहराने के लिए यह वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

दादा तबीयत तो ठीक है ना! नहीं कभी–कभी इस उम्र में हो जाता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था, जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। भारत पर भांति–भांति के दबाव डाल रहे थी, भांति–भांति के ज़ुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, त्रश्स्त्र स्ड्ढ1द्व अद्धद्व त्क्षद्वद्वड्ड, इसको भारत में घर–घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद, 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा, तो उस गीत का उसमें समावेश किया गया।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था, जो हजारों वर्ष से भारत की रग–रग में रचा–बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ, वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी।

वंदे मातरम, यह सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, सिर्फ हम अंग्रेज जाएं और हम खड़े हो जाएं, अपनी राह पर चलें, इतनी मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, वो उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार–बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं, तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है 卐माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः卐 अर्थात यह भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यही वह विचार है, जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था 卐जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी卐। वंदे मातरम, यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की, तो स्वाभाविक ही वह स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण वंदे, मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्?तुति में लिखा गया था, 卐मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है, ये शब्द हैं वंदे मातरम, है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है, यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्?तस्?थलि को चीरकर वीर का अभिमान है, यह शब्द वंदे मातरम।卐

आदरणीय अध्यक्ष जी,

कुछ दिन पूर्व, जब वंदे मातरम 150 का आरंभ हो रहा था, तो मैंने उस आयोजन में कहा था, वंदे मातरम हजारों वर्ष की सांस्?कृतिक ऊर्जा भी थी। उसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत का विजन भी था। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी, भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सकें, ऐसी एक फैशन बन गई थी और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे, वह लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झंकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए, वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली रूप को प्रकट करते हुए, आपने लिखा था, त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी, कमला कमलदलविहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलाम्, अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥ अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी हैं और दुश्मनों के सामने अस्त्र–शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी हैं।

अध्यक्ष जी,

यह शब्द, यह भाव, यह प्रेरणा, गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। इन वाक्यों ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया की लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है, यह गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं थी, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

वंदे मातरम, इसका जो जन–जन से जुड़ाव था, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक लंबी गाथा अभिव्यक्त होती है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

जब भी जैसे किसी नदी की चर्चा होती है, चाहे सिंधु हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, उस नदी के साथ एक सांस्कृतिक धारा प्रवाह, एक विकास यात्रा का धारा प्रवाह, एक जन–जीवन की यात्रा का प्रवाह, उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावनाओं से गुजरता था। उसके तट पर पल्लवित होता था, ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कभी उपलब्ध नहीं होगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था और जिस प्रकार से वह अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा कि जब तक, जब तक भारत को बाटेंगे नहीं, जब तक भारत को टुकडों में नहीं बाटेंगे, भारत में ही लोगों को एक–दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है और अंग्रेजों ने बाटों और राज करो, इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया क्यूंकि अंग्रेज़ भी जानते थे, वह एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्?य देश को दिशा देता था, देश को ताकत देता था, देश को प्रेरणा देता था और इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का यह जो सामर्थ्?य है, वह पूरे देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है। और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। और अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया, तो यह देश भी टूट जाएगा और वो यावच चन्द्र–दिवाकरौ राज करते रहेंगे, यह उनकी सोच थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में यह पाप किया, तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली–गली का नाद बन गया था और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीज और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी, लेकिन वंदे मातरम एक स्वर, एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला, बंकिम दा का यह भाव सूत्र, बंकित बाबू बोलें अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने, बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा थैंक यू, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको ऐतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने यह जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा, उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया और अंग्रेजों ने देखिए कितनी कमजोरी होगी और इस गीत की ताकत कितनी होगी, अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाने पर सजा, छापने पर सजा, इतना ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा, इतने कठोर कानून लागू कर दिए गए थे। हमारे देश की आजादी के आंदोलन में सैकड़ों महिलाओं ने नेतृत्व किया, लक्ष्यावधि महिलाओं ने योगदान दिया। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, बारीसाल, बारीसाल में वंदे मातरम गाने पर सर्वाधिक जुल्म हुए थे। वो बारीसाल आज भारत का हिस्सा नहीं रहा है और उस समय बारीसाल के हमारे माताएं, बहने, बच्चे मैदान उतरे थे, वंदे मातरम के स्वाभिमान के लिए, इस प्रतिबंध के विरोध में लड़ाई के मैदान में उतरी थी और तब बारीसाल कि यह वीरांगना श्रीमती सरोजिनी घोष, जिन्होंने उस जमाने में वहां की भावनाओं को देखिए और उन्होंने कहा था की वंदे मातरम यह जो प्रतिबंध लगा है, जब तक यह प्रतिबंध नहीं हटता है, मैं अपनी चूड़ियां जो पहनती हूं, वो निकाल दूंगी। भारत में वह एक जमाना था, चूड़ी निकालना यानी महिला के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना हुआ करती थी, लेकिन उनके लिए वंदे मातरम वह भावना थी, उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां, जब तक वंदे मातरम प्रतिबंध नहीं हटेगा, मैं दोबारा नहीं धारण करूंगी, ऐसा बड़ा व्रत ले लिया था। हमारे देश के बालक भी पीछे नहीं रहे थे, उनको कोड़े की सजा होती थी, छोटी–छोटी उम्र में उनको जेल में बंद कर दिया जाता था और उन दिनों खास करके बंगाल की गलियों में लगातार वंदे मातरम के लिए प्रभात फेरियां निकलती थी। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और उस समय एक गीत गूंजता था बंगाल में जाए जाबे जीवोनो चोले, जाए जाबे जीवोनो चोले, जोगोतो माझे तोमार काँधे वन्दे मातरम बोले (द्वड्ड ब्क्ष्द्वड्डदड्डद्यद्व) अर्थात हे मां संसार में तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए, तो वह जीवन भी धन्य है, यह बंगाल की गलियों में बच्चे कह रहे थे। यह गीत उन बच्चों की हिम्मत का स्वर था और उन बच्चों की हिम्मत ने देश को हिम्मत दी थी। बंगाल की गलियों से निकली आवाज देश की आवाज बन गई थी। 1905 में हरितपुर के एक गांव में बहुत छोटी–छोटी उम्र के बच्चे, जब वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, अंग्रेजों ने बेरहमी से उन पर कोड़े मारे थे। हर एक प्रकार से जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इतना अत्याचार हुआ था। 1906 में नागपुर में नील सिटी हाई स्कूल के उन बच्चों पर भी अंग्रेजों ने ऐसे ही जुल्म किए थे। गुनाह यही था कि वह एक स्वर से वंदे मातरम बोल करके खड़े हो गए थे। उन्होंने वंदे मातरम के लिए, मंत्र का महात्म्य अपनी ताकत से सिद्ध करने का प्रयास किया था। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, रोशन सिंह, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते–कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए यह अलग–अलग जेलों में होता था, अलग–अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे। जिन पर जुल्म हो रहा था, उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत, श्रेष्ठ भारत, इन सबका मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। चटगांव की स्वराज क्रांति जिन युवाओं ने अंग्रेजों को चुनौती दी, वह भी इतिहास के चमकते हुए नाम हैं। हरगोपाल कौल, पुलिन विकाश घोष, त्रिपुर सेन इन सबने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मास्टर सूर्य सेन को 1934 में जब फांसी दी गई, तब उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र लिखा और पत्र में एक ही शब्द की गूंज थी और वह शब्द था वंदे मातरम।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए, दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भाव गीत नहीं हो सकता, जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि–कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हों, दुनिया में ऐसा कोई भाव गीत नहीं हो सकता, जो वंदे मातरम है। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे, जो इस प्रकार के भाव गीत की रचना कर सकते थे। यह विश्व के लिए अजूबा है, हमें गर्व से कहना चाहिए, तो दुनिया भी मनाना शुरू करेगी। यह हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, यह बलिदान का मंत्र था, यह ऊर्जा का मंत्र था, यह सात्विकता का मंत्र था, यह समर्पण का मंत्र था, यह त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का यह मंत्र था और वह मंत्र वंदे मातरम था। और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उन्होंने लिखा था, एक कार्ये सोंपियाछि सहस्त्र जीवन–वन्दे मातरम् (द्वड्ड ब्क्ष्द्वड्डदड्डद्यद्व) अर्थात एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम। यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

उसी कालखंड में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग दुनिया के अलग–अलग भागों में पहुंची और लंदन में जो क्रांतिकारियों की एक प्रकार से तीर्थ भूमि बन गया था, वह लंदन का इंडिया हाउस वीर सावरकर जी ने वहां वंदे मातरम गीत गाया और वहां यह गीत बार–बार गूंजता था। देश के लिए जीने–मरने वालों के लिए वह एक बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर रहता था। उसी समय विपिन चंद्र पाल और महर्षि अरविंद घोष, उन्होंने अखबार निकालें, उस अखबार का नाम भी उन्होंने वंदे मातरम रखा। यानी डगर–डगर पर अंग्रेजों के नींद हराम करने के लिए वंदे मातरम काफी हो जाता था और इसलिए उन्होंने इस नाम को रखा। अंग्रेजों ने अखबारों पर रोक लगा दी, तो मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में एक अखबार निकाला और उसका नाम उन्होंने वंदे मातरम रखा!

आदरणीय अध्यक्ष जी,

वंदे मातरम ने भारत को स्वावलंबन का रास्ता भी दिखाया। उस समय माचिस के डिबिया, मैच बॉक्स, वहां से लेकर के बड़े–बड़े शिप उस पर भी वंदे मातरम लिखने की परंपरा बन गई और बाहरी कंपनियों को चुनौती देने का एक माध्यम बन गया, स्वदेशी का एक मंत्र बन गया। आजादी का मंत्र स्वदेशी के मंत्र की तरह विस्तार होता गया।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं एक और घटना का जिक्र भी करना चाहता हूं। 1907 में जब वी ओ चिदंबरम पिल्लई, उन्होंने स्वदेशी कंपनी का जहाज बनाया, तो उस पर भी लिखा था वंदेमातरम। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम को तमिल में अनुवाद किया, स्तुति गीत लिखे। उनके कई तमिल देशभक्ति गीतों में वंदे मातरम की श्रद्धा साफ–साफ नजर आती है। शायद सभी लोगों को लगता है, तमिलनाडु के लोगों को पता हो, लेकिन सभी लोगों को यह बात का पता ना हो कि भारत का ध्वज गीत वी सुब्रमण्यम भारती ने ही लिखा था। उस ध्वज गीत का वर्णन जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, तमिल में इस ध्वज गीत का शीर्षक था। अद्धड्ड4द्वड्ड द्वड्डद्वद्व्रश्स्त्रद्व श्चड्डद्धद्वद्धह्न, ह्लद्धड्ड5द्धड्डस्त्रह्न श्चड्डड्ड–द्वड्डह्लद्ध क्द्ध्रड्ड5द्धड्डह्लद्धद्वस्त्रड्ड ङ्कड्डद्धद्वद्वह्न! (द्वड्ड अड्डद्वद्वद्य) अर्थात देश प्रेमियों दर्शन कर लो, सविनय अभिनंदन कर लो, मेरी मां की दिव्य ध्वजा का वंदन कर लो।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आज इस सदन में वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावनाएं क्या थी, वह भी रखना चाहता हूं। दक्षिण अफीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन और और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 जो लिखा था, उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, 卐गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुईं, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया।卐 गांधी जी आगे लिखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, वह लिखते हैं यह 1905 की बात है। उन्होंने लिखा, 卐यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है, जैसे यह हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान हैं और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है।卐

अध्यक्ष जी,

जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में, जो भी देश के लिए जीता–जागता, जिस देश के लिए जागता था, उन सबके लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? यह अन्याय क्यों हुआ? वह कौन सी ताकत थी, जिसकी इच्छा खुद पूज्?य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। मैं समझता हूं कि आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व बना रहे हैं, यह चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीडिया को जरूर बताना हमारा दायित्व है। जिसकी वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम भी यह जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का क्वोट पढ़ता हूं, नेहरू जी कहते हैं 卐मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पड़ा है।卐 नेहरू जी फिर लिखते हैं, 卐मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे।卐

साथियों,

इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था, पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने–कोने में प्रभात फेरियां निकालीं, वंदे मातरम गीत गाया लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, यह तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया और कांग्रेस का यह तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है, कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के नीतियां वैसी की वैसी ही हैं और इतना ही नहीं द्बह्लष्ट चलते–चलते रूस्ष्ट हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन–जिन के नाम के साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब, वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

किसी भी राष्ट्र का चरित्र उसके जीवटता उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा, जब चुनौतियों का कालखंड होता है, जब संकटों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती हैं, उजागर होती हैं और सच?चे अर्थ में कसौटी से कसी जाती हैं। जब कसौटी का काल आता है, तब ही यह सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश के प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता, वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब–जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। बीच का कालखंड कैसा गया, जाने दो। लेकिन आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ वो भाव दिखता है। तिरंगे झंडे फहरते हैं। एक जमाना था, जब देश में खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था, मेरे देश के किसानों के अन्?न के भंडार भर दिए और उसके पीछे भाव वही है वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलना की कोशिश हुए, संविधान की पीठ पर छुरा घोप दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंद मातरम का भाव था, देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा लहराता रहा, विजय श्री प्राप्त करता रहा। कोरोना जैसा वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ा।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यह राष्ट्र की शक्ति है, यह राष्ट्र को भावनाओं से जोड़ने वाला सामर्थ्?यवान एक ऊर्जा प्रवाह है। यह चेतना परवाह है, यह संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब है, उसका प्रकटीकरण है। यह वंदे मातरम हमारे लिए सिर्फ स्मरण करने का काल नहीं, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा का लेने का काल बन जाए और हम उसके प्रति समर्पित होते चलें और मैंने पहले कहा हम लोगों पर तो कर्ज है वंदे मातरम का, वही वंदे मातरम है, जिसने वह रास्ता बनाया, जिस रास्ते से हम यहां पहुंचे हैं और इसलिए हमारा कर्ज बनता है। भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्?य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम यह सिर्फ गीत या भाव गीत नहीं, यह हमारे लिए प्रेरणा है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, उसको पूरा करना है। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है। हम स्वदेशी आंदोलन को ताकत देना चाहते हैं, समय बदला होगा, रूप बदले होंगे, लेकिन पूज्य गांधी ने जो भाव व्यक्त किया था, उस भाव की ताकत आज भी हमें मौजूद है और वंदे मातरम हमें जोड़ता है। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का, देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का, आजाद भारत के सपने को सींचा था वंदे भारत की भावना ने, वंदे भारत की भावना ने, समृद्ध भारत के सपने को सींचेगा वंदे मातरम के भवना, उसी भावनाओं को लेकर के हमें आगे चलना है। और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना, 2047 में देश विकसित भारत बन कर रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं। इसी मंत्र और इसी संकल्प के साथ वंदे मातरम हमें प्रेरणा देता रहे, वंदे मातरम का हम ऋण स्वीकार करें, वंदे मातरम की भावनाओं को लेकर के चलें, देशवासियों को साथ लेकर के चलें, हम सब मिलकर के चलें, इस सपने को पूरा करें, इस एक भाव के साथ यह चर्चा का आज आरंभ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सदनों में देश के अंदर वह भाव भरने वाला कारण बनेगा, देश को प्रेरित करने वाला कारण बनेगा, देश की नई पीढ़ी को ऊर्जा देने का कारण बनेगा, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद!

नारी शक्ति से विकास–महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रगति पर फोकस करने की ज़रूरत

लक्ष्मी पुरी

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हमारे उज्जवल आज और बदलते कल के लिए बेहद ज़रुरी आधार है। तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते इस वक्त में हम लैंगिक समानता हासिल करने के लिए एक और शताब्दी तक इंतज़ार नहीं कर सकते। नारी शक्ति और भारत की विश्व को सभ्यतागत देन, महिलाओं को देवी के रूप में देखने की मूल अवधारणा को अब महज़ एक प्रतीक से आगे ले जाकर व्यावहारिक जीवन में लाना होगा और महिलाओं के प्रति सम्मान की हमारी विरासत को महिलाओं के नेतृत्व वाले सतत् विकास के मार्ग पर ले जाना होगा।

जब आधी मानवता की स्वतंत्रता और जीवन जीने के अवसर बढ़ते हैं, तो नए समाज में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। लैंगिक समानता अपने आप में एक आदर्श विचार है, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और पर्यावरणीय प्रगति का एक शक्तिशाली कारक भी है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2015 की रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2024 का विश्लेषण और ईवाय का इंडिया@100 कार्य, मिलकर एक ठोस आर्थिक तर्क पेश करते हैं- लैंगिक अंतर को कम करने से सकल घरेलू उत्पाद में 20 से 30% की वृद्धि हो सकती है और यह भारत के लिए 2047 तक 28 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बेहद ज़रुरी है।

भारत एक जनसांख्यिकीय दौर से गुज़र रहा है। हमारी युवा आबादी का तभी लाभ उठाया जा सकता है, जब वह महिलाओं के लिए फायदेमंद हो। प्रजनन क्षमता घट रही है और लड़कियों तथा युवतियों की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ रही हैं, भारत अब उच्च शिक्षा में लगभग बराबरी पर है और करीब 43% स्टेम छात्राएँ हैं। कई सालों तक महिलाओं के काम को अनौपचारिक और अदृश्य बनाए रखने के बाद, आखिरकार महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी फिर से बढ़ने लगी है और अब इसे बेहतर गुणवत्ता, औपचारिक और भविष्य के लिए तैयार नौकरियों में तब्दील होना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक खास विशेषता ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों को लक्षित करना है, जिनमें महिलाएँ प्रमुख लाभार्थी हैं। इसके अलावा बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ऐसे कार्यक्रम भी सरकार के फोकस में हैं, जो लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील हैं। छात्रवृत्ति, छात्रावास और आरक्षित सीटों ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाया है और ज्ञान, स्वास्थ्य, हरित और देखभाल अर्थव्यवस्थाओं में उनके लिए नए रास्ते खोले हैं। डिजिटल मिशन और ग्रामीण कार्यक्रमों ने करोड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और उनके हाथों में किफायती डेटा वाले स्मार्टफोन और जन धन खाते दिए हैं, जिससे उन्हें सूचना, बाज़ार और सेवाओं तक सीधी पहुँच मिली है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा, स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास जैसी प्रमुख योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा, ऋण तक पहुँच, स्वच्छता और सुरक्षित आवास जैसी सुविधाएं दी हैं, जबकि सुकन्या समृद्धि और लखपति दीदी जैसी योजनाओं ने उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और उनकी आय में बढ़ोत्तरी को मुमकिन बनाया है। अब अगले स्तर पर उन्हें निर्णायक रूप से लाभार्थी से अधिकार पति, यानी अधिकारों के प्राप्तकर्ता से पूर्ण अधिकार धारक और अर्थव्यवस्था तथा समाज में फैसला लेने वाली महिला के रूप में स्थापित करना होगा। 2030 तक लैंगिक समानता पर सतत् विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त करने का यही असल सार है।

भारत में अंतर्संबंध का अर्थ है, कि कई महिलाओं को गरीबी, जाति, जनजाति, धर्म, दिव्यांगता या स्थान के कारण कई स्तरों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तीन तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं के विवाह अधिकारों को मज़बूत किया है। जनजातीय पृष्ठभूमि की महिला, द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव इस बात का प्रतीक है कि हाशिए पर रहने वाले समाज की महिला एक गणतंत्र में किस ऊँचाई तक पहुँच सकती है और लैंगिक और सामाजिक न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और गहरा कर सकती है। मौजूदा वक्त में हमें जिस कल का निर्माण करना है, वह ऐसा होना चाहिए, जिसमें विकास के ऐसे उदाहरण, असाधारण न होकर, व्यवस्था का हिस्सा हों और व्यापक रुप से दिखाई दें।

हिंसा से मुक्ति, एक लैंगिक समानता वाले समाज का अनिवार्य आधार बनी हुई है। घरेलू दुर्व्यवहार और मानव तस्करी से लेकर कार्यस्थल पर उत्पीड़न और ऑनलाइन घृणा तक, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा को खत्म करना, हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए, साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य और यौन तथा प्रजनन अधिकारों पर निरंतर काम करना चाहिए, जो स्वायत्तता और सम्मान की गारंटी देते हैं।

राजनीतिक आवाज़ और नेतृत्व हर दूसरे हस्तक्षेप के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं और महिलाओं को भविष्य के नियमों को आकार देने की ताकत देते हैं। जमीनी स्तर पर, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में 33% से 50% आरक्षण ने 15 लाख महिला नेताओं को जन्म दिया है। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कानून निर्माण और शासन में वास्तविक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जैसा कि हाल ही में बिहार में देखा गया, महिलाएँ चुनावी नतीजों को भी नया रूप दे रही हैं, जहाँ जागरूक मतदाता सुरक्षा, गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाली सरकारों को चुन रहे हैं।

संस्कृति एक बुनियादी ढाँचा है, जिसके ज़रिए कोई भी समाज खुद को समझता है और अपने भविष्य की कल्पना करता है। सदियों से, इसका निर्माण पितृसत्ता के पुरुषवादी दृष्टिकोण से हुआ है, यहाँ तक कि उन सभ्यताओं में भी जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती थी। आज, मीडिया और साहित्य से लेकर सिनेमा, संगीत, खेल और डिजिटल सामग्री तक, रचनात्मक उद्योगों में महिलाएँ उस पटकथा को नए सिरे से लिख रही हैं और देवी के विचार को दोबारा एक नई परिभाषा दे रही हैं, ताकि उनके प्रति श्रद्धा को घर, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र में समान अधिकार, समान सम्मान और साझा ज़म्मिदारी के रूप में दर्शाया जा सके।

परिवर्तन के अगले स्तर का नेतृत्व अब संसदों के साथ–साथ कार्यालयों, बोर्ड रूम, प्रयोगशालाओं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से भी होना चाहिए। सरकारी विभागों और राजनीतिक दलों से लेकर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान परिषदों, स्टार्टअप्स और बड़े निगमों तक, हर संस्थान को लैंगिक समानता को अपने डीएनए में शामिल करना होगा। इसका अर्थ है कि लैंगिक समानता वाली शिक्षा से लेकर नौकरियों की मूल्य श्रृंखला तक, जहाँ लड़कियाँ कक्षाओं से आगे बढ़कर व्यापक उद्योग 4.0 व्यवस्था तंत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में करियर बना सकें। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि कॉर्पोरेट नेता और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भर्ती, प्रतिधारण, दोबारा प्रवेश और पदोन्नति में समानता के लिए प्रतिबद्ध हों और वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड में और ज्यादा महिलाओं को शामिल करें। इसके लिए एक शोध और नवाचार प्रणाली और एक स्टार्टअप संस्कृति को तैयार करना होगा, जहां महिला संस्थापक, वैज्ञानिक और रचनाकार समान शर्तों पर ऋण, मार्गदर्शन और बाज़ार तक पहुँच सकें।

जी–20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को एजेंडे के केंद्र में रखा, डिजिटल लैंगिक अंतर को पाटने, महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी बढ़ाने और महिला उद्यमिता और नेतृत्व का विस्तार करने की प्रतिबद्धताएँ ज़ाहिर कीं। सशक्त महिलाएँ हमारे युग की महान बदलावकारी शक्ति हैं। अपने परिवारों, समुदायों, देशों और दुनिया को बदलने वाली परिवर्तित महिलाओं के रूप में, वे जनसांख्यिकीय लाभ उठाते हुए महिलाओं और लड़कियों को आज़ादी, विकल्प और सम्मान से जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं। भारत अगर इस आंदोलन को इसी रफ्तार से आगे बढ़ाता है, तो एक अग्रणी शक्ति के रूप में इसकी दूसरी पारी की शुरूआत, 2047 तक विकसित भारत की यात्रा से शुरू होगी, वो यात्रा जो नारी शक्ति द्वारा प्रज्वलित और संचालित होगी।

लेखिका संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और लैंगिक समानता तथा महिला–नेतृत्व वाले विकास की एक अग्रणी वैश्विक समर्थक हैं। लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके व्यक्तिगत विचार हैं।

कुवि एलुमनी विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर – प्रो. सोमनाथ सचदेवा

कुवि सांख्यिकी विभाग द्वारा स्मृतिगंध 2.0 का भव्य आयोजन

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

कुरुक्षेत्र, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक = कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च विभाग द्वारा आयोजित एलुमनी मीट 卐स्मृतिगंध 2.0卐 शानदार और गरिमामय माहौल में सम्पन्न हुई। इस भव्य आयोजन में यूएसए और चीन सहित देश विदेश से आए पूर्व छात्रों ने भाग लिया और विभाग के सुनहरे दिनों को याद करते हुए भावपूर्ण अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। विभाग की यात्रा और उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की गई, जिसने सभी को पुराने समय की मधुर यादों में डूबा दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि विश्वविद्यालय की सच्ची पहचान उसके एलुमनी होते वो विश्वविद्यालय के ब्रांड अम्बेसडर होते हैं। विश्विद्यालय का गौरव इस बात में है कि इसके विद्यार्थी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं।卐 उन्होंने वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में सांख्यिकी, रिसर्च, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के इस आधुनिक युग में सांख्यिकी की भूमिका अत्यंत अहम हो गई है। उन्होंने कहा कि एआई की पूरी नींव डेटा पर आधारित होती है और उस डेटा को समझने, विश्लेषण करने तथा उससे सार्थक निष्कर्ष निकालने का कार्य सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, व्यवहार विश्लेषण जैसे सभी क्षेत्रों में सांख्यिकीय विधियों का व्यापक उपयोग हो रहा है। सांख्यिकी न केवल डेटा की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है, बल्कि एआई मॉडल की सटीकता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता को भी मजबूत बनाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एआई के विकास और उसके सफल उपयोग में सांख्यिकी एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रही है।

कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने यह भी कहा कि स्मृतिगंध 2.0' जैसे आयोजन केवल पुनर्मिलन नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और अनुभव के आदान प्रदान के मंच हैं। उम्मीद है कि एलुमनी भविष्य में भी विश्वविद्यालय के शोध और शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान देंगे।卐

विभागाध्यक्ष प्रो. एम.एस. कादियान ने सभी का स्वागत करते हुए अपने आत्मीय संबोधन में कहा कि एलुमनी किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनका अनुभव और मार्गदर्शन वर्तमान छात्रों के लिए अमूल्य है। हमारा उद्देश्य विभाग और अपने पूर्व छात्रों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखना है।卐

पूर्व छात्रों यूएसए से डॉ. परमजीत सिंह विर्क, चीन से प्रो. ब्रिज मोहन, आईएसएस मुकेश आहूजा ने ने अपने अंतरराष्ट्रीय अनुभव, तकनीकी कौशल और ग्लोबल मार्केट में बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मिली शिक्षा और वातावरण ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री हरीश कुमार, डायरेक्टर वूर्टजाइट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा डाटा एनालिटिक्स और एआई और स्टैटिसटिकल मॉडलिंग आने वाले वर्षों का भविष्य है। आज इंडस्ट्री स्किल्ड डेटा प्रोफेशनल्स की तलाश में है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के के छात्र इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।卐उन्होंने छात्रों को नवाचार, सीखने और नई तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा दी। विभाग के वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षकों प्रो. एन.के जैन, प्रो. आरएल गर्ग, प्रो. एसडी शर्मा ने भी विभाग की स्थापना, संघर्ष और उपलब्धियों के प्रेरक किस्से सुनाए, जिन्हें एलुमनी ने खड़े होकर तालियों से सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। डॉ. जितेंद्र कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और सभी की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। पहले सत्र का समापन राष्ट्रीय गान और सामूहिक ग्रुप फोटो के साथ हुआ।

दोपहर के सत्र में एलुमनी ने आपसी संवाद के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। एलुमनी ने विभाग का विस्तृत भ्रमण किया और विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को सराहा।

इसके बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। स्मृतिगंध 2.0卐 न केवल एक सफल आयोजन रहा, बल्कि विभाग और एलुमनी के बीच मजबूत संवाद का सेतु बनकर उभरा। यह दिन सभी के लिए यादगार, भावनापूर्ण और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

इस अवसर पर प्रो. एलुमनी एसोसिएशन के निदेशक प्रो. अनिल मित्तल, प्रो. परमेश कुमार, प्रो. दीपक राय बब्बर, डॉ गुरचरण सिंह,डॉ. जोरावर, डॉ. सत्यभूषण, संजय चौधरी, हरमुनीश तनेजा, नवदीप, अनुज, नीता, विजय, विनोद शर्मा आदि मौजूद रहे।

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ब्राह्मण सभा को दिया निमंत्रण

सभा के गौ सेवा प्रोजेक्ट को चलते हुए 15 महीने पूरे

मनदीप कौर

मोगा पंजाब दिसंबर [कैप्टन सुभाष शर्मा, ब्यूरो चीफ]= ब्राह्मण सभा, मोगा की कार्यकारिणी ने अपने 卐गौ सेवा प्रोजेक्ट卐 के तहत आज स्वामी महेश मुनी (बोरे वाले) जी की गौशाला में जा कर गौ सेवा की। सभा के अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप भारती व सदस्यो ने गौशाला मे गौमाता को हरा चारा व गुड़ आदि खिलाया। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से यह प्रोजेक्ट पिछले 15 महीने से लगातार चल रहा है।जिस पर सभा की ओर से 20 हजार के करीब राशि गौ सेवा के लिए खर्च की गई है।उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में गाय को पुज्यनीय माना गया है। इस अवसर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्थानीय चेयरमैन राजेश शर्मा राजू, अध्यक्ष महेश गर्ग,वार्ड प्रधान मंगत राम शर्मा व उनकी टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ प्रवीण भाई तोगड़िया जी के मोगा आगमन संबंधी समारोह की चर्चा करते हुए ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप भारती व उनकी कार्यकारिणी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र दिया। महेश गर्ग ने कहा कि प्रवीण भाई हिंदू भाईचारे में एकता, आपसी प्रेम प्यार व धर्म का संदेश लेकर भारत यात्रा पर निकले है।उन्होंने सभी से इस 22 दिसंबर के प्रोग्राम में शामिल होने का आग्रह किया। इस अवसर पर कैप्टन सुभाष चन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष रविनंदन शर्मा, महासचिव विजय शर्मा, जसप्रीत शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, भजन गायक रामचंद्र शर्मा, नितिन शर्मा, टीनू दात्तेवाल, डिम्पी शर्मा, प्रदीप शर्मा (नैस्ले), विजय मिश्रा, बलराज शर्मा, आशू, पंडित जयदेव आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर किया नमन

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को संविधान निर्माता और आधुनिक भारत के शिल्पी डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के विचार, सिद्धांत और संघर्ष न केवल भारतीय समाज बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं। उनके जीवन का हर अध्याय हमें यह सीख देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ इच्छाशक्ति, शिक्षा और समानता के प्रति समर्पण से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने भारत के संविधान में न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया बल्कि समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने की नींव रखी। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया और शिक्षा को सामाजिक उन्नति का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की शिक्षाएं और उनके विचार समाज को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। समानता, न्याय और मानवाधिकारों के प्रति उनका अदम्य संकल्प हमारे मार्ग को निरंतर प्रकाशमान करता रहेगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार डॉ. अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए समाज के वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी नीतियाँ चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को डॉ. अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

बाबा साहेब की शिक्षाएं समाज को सदैव करती रहेंगी प्रेरित – मुख्यमंत्री, समानता, न्याय और मानवाधिकारों के प्रति बाबा साहेब का अदम्य संकल्प हमारी पीढ़ियों को देता रहेगा सही दिशा – मुख्यमंत्री

गुरू नानक मिशन चौक को मिली नई लुक

कैबिनेट मंत्री, मेयर और सलाहकार पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग ने नया स्वरूप देने के बाद चौक जनता को किया समर्पित

एस. के. सक्सैना

जालंधर, ॱ शहर के प्रमुख गुरू नानक मिशन चौक, जिसे नया लुक दिया गया है, उसे आज पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत, मेयर विनीत धीर और पंजाब पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के सलाहकार दीपक बाली द्वारा जनता को समर्पित किया गया। इस मौके पर सीनियर 'आप' नेता नितिन कोहली भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री, मेयर और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के सलाहकार ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शहर भर के प्रमुख चौकों और चौराहों के नवीनीकरण के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत कई चौकों का पहले ही सौंदर्यीकरण और आधुनिक डिजाइनों के साथ कायाकल्प किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इन अपग्रेड किए गए चौकों के लंबे समय तक रख–रखाव को सुनिश्चित

करने के लिए कई निजी संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नवीनीकृत चौक न केवल यात्रियों को ताजगी भरा और सुहावना दृश्य प्रदान करेगा बल्कि शहर की सुंदरता बढ़ाने में भी योगदान देगा। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर नगर निगम की नवीनीकरण मुहिम की अगुवाई करने के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि नगर निगम की सक्रिय भूमिका ने शहर की दशा और दिशा को और बेहतर बनाया है। उन्होंने अधिकारियों को इन चौकों के रख–रखाव की नियमित निगरानी करने और इस कार्य के लिए जिम्मेदार सहयोगी संगठनों के साथ तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन चौकों की सुंदरता आने वाले वर्षों तक बरकरार रहे। उन्होंने आगे कहा कि शहरवासियों को जल्द ही कई अन्य चौकों का बड़े पैमाने पर बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा, जिससे जालंधर को एक नयी और आधुनिक लुक मिलेगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पंचकूला में उत्सव, संचार और करियर पर आधारित आईआईएसएफ विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया

मंत्री महोदय ने कहा– भारत में आत्मनिर्भर विज्ञान को बढ़ावा जारी, विज्ञान में आत्मनिर्भरता अब केवल आकांक्षा नहीं रही

पंकज

पंचकूला, 6 दिसंबरॱ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज हरियाणा के पंचकूला में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएस) का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे तीन फ्सीफ् – उत्सव, संचार और करियर – के आस–पास परिभाषित किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति प्रयोगशालाओं से आगे बढ़नी चाहिए और नागरिकों, छात्रों और युवा पेशेवरों को सार्थक तरीके से इसमें शामिल करना चाहिए। इस महोत्सव का 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की परिकल्पना एक नियमित शैक्षणिक सम्मेलन के रूप में नहीं, बल्कि एक खुले, जन–केंद्रित मंच के रूप में की गई है जो विज्ञान को लोगों के करीब लाता है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लक्षित लाभार्थियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है, जो विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय और सामंजस्य पर सरकार के प्रयास को प्रदर्शित करता है। तीन फ्सीफ् के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि आईआईएसएफ भारत की वैज्ञानिक यात्रा और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का उत्?सव मनाता है, शैक्षणिक और शोध संस्थानों से परे वैज्ञानिक ज्ञान का संचार करता है, और युवा प्रतिभागियों के लिए करियर की खोज के एक मंच के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि छात्रों, शोधकर्ताओं और पहली बार सीखने वाले छात्रों को महोत्सव के दौरान संरचित सत्रों के साथ–साथ अनौपचारिक नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्योग में उभरते अवसरों से परिचित होने का अवसर मिलता है। आईआईएसएफ को विकसित भारतश्च2047 के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत रखते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की नींव रखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में, भारत ने विज्ञान के प्रति एक मिशन–संचालित वि?ज़न अपनाया है, जिसे सुधारों, बुनियादी ढाँचे में बढ़े हुए निवेश और प्रतिभा विकास पर ज़ोर देने से बल मिला है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक प्रगति अब सीधे तौर पर शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा दे रही है, जिसमें बेहतर मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों से लेकर ध्रुवीय अनुसंधान और डिजिटल तकनीकें शामिल हैं। आईआईएसएफ 2025 की थीम फ्विज्ञान से समृद्धिॱ आत्मनिर्भर भारत की ओरफ् का उल्लेख करते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि विज्ञान में आत्मनिर्भरता धीरे–धीरे आकार ले रही है। उन्होंने स्वदेशी स्तर पर प्रमुख वैज्ञानिक संपत्तियों के निर्माण की पहलों पर

प्रकाश डाला, जिनमें एक बहुउद्देशीय, सभी मौसमों में काम करने वाला अनुसंधान पोत, जिसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है, और देश का चल रहा मानव पनडुब्बी कार्यक्रम शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्थान जलवायु डेटा और मॉडल भी प्रदान कर रहे हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने नवाचार, अनुसंधान उत्पादन और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बेहतर वैश्विक स्थिति पर प्रकाश डाला और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, निवासी भारतीयों द्वारा पेटेंट आवेदनों में वृद्धि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में मान्यता का हवाला दिया। उन्होंने चंद्रयान–3 मिशन, कोविड–19 महामारी के दौरान स्वदेशी वैक्सीन विकास और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति जैसी उपलब्धियों का उल्लेख अनुसंधान के मजबूत परिणाम देने वाले उदाहरणों के रूप में किया।

युवाओं तक पहुँच बढ़ाने पर ज़ोर देते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि आईआईएसएफ की गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों और युवा शोधकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में करियर के बारे में समझ को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि आज अवसर सरकारी रोज़गार से कहीं आगे बढ़कर स्टार्टअप, उद्योग–आधारित अनुसंधान और अनुप्रयुक्त नवाचार तक फैले हुए हैं। क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, नीली अर्थव्यवस्था और गहन तकनीकी उद्यमिता जैसे क्षेत्रों पर सत्र इस वर्ष के कार्यक्रम का हिस्सा हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योग के बीच मज़बूत सहयोग के महत्व पर भी ज़ोर दिया और कहा कि जब नीतिगत समर्थन, वित्त पोषण और उद्यम मिलकर काम करते हैं, तो नवाचार फलता–फूलता है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी को और अधिक बढ़ाने की अनुमति देने वाले हालिया नीतिगत उपायों का उद्देश्य एक अधिक सक्षम नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। मंत्री महोदय ने उद्घाटन कार्यक्रम में विज्ञान–प्रौद्योगिकी–रक्षा–अंतरिक्ष प्रदर्शनी और फ्विज्ञान पर एक क्षेत्रफ् प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो इंटरैक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से वैज्ञानिक क्षमताओं और चल रहे अनुसंधान को प्रदर्शित करती है। उन्होंने अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र, भारती के शोधकर्ताओं के साथ लाइव इंटरफ़ेस के माध्यम से बातचीत भी की और चरम ध्रुवीय परिस्थितियों में किए जा रहे वैज्ञानिक कार्यों की समीक्षा की, जिसमें भारत के बढ़ते ध्रुवीय अनुसंधान प्रयासों और स्वदेशी क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। अगले चार दिनों में आयोजित होने वाले प्रदर्शनियों, व्याख्यानों और इंटरैक्टिव सत्रों के साथ, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य विज्ञान के साथ जनता की सहभागिता को गहरा करना है, साथ ही अनुसंधान, नवाचार और मानव संसाधन विकास में दीर्घकालिक राष्ट्रीय उद्देश्यों में योगदान देना है।

ध्रुवीय अनुसंधान से लेकर डीप टेक तक, आईआईएसएफ भारत के विस्तृत विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है

केंद्रीय सूचना और प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन जालंधर पहुंचे

मनदीप कौर

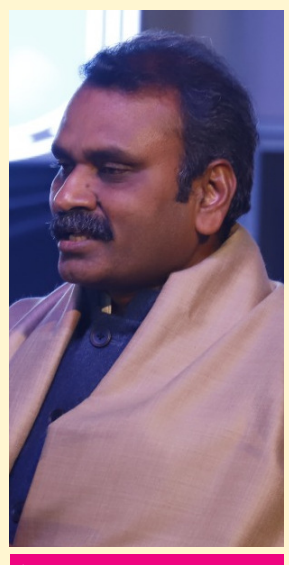

जालंधर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन जालंधर पहुंचे। अपने एक दिन के दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम में बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी और एक स्थानीय स्कूल के सालाना कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि न्याय और समानता के प्रति डॉ. अंबेडकर जी का अटूट समर्पण भारत को रास्ता दिखाता रहेगा। डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि डॉ. अंबेडकर जी ने अपने संघर्ष भरे जीवन में हमेशा समाज के हर तरह के विकास के लिए काम किया, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मंत्री ने कहा कि स्कूल में छुआछूत का सामना करने के बावजूद, डॉ. अंबेडकर खुद बैरिस्टर बने और देश और दबे–कुचले समाज की सेवा करने के लिए लंदन से भारत लौट आए।श्री मुरुगन ने कहा कि संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन होने के अलावा, वे एक जाने–माने अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कई बड़े संस्थानों और फ्क्ष्ठ्रश्चश्चफ् का नाम डॉ. अंबेडकर जी के नाम पर रखा है, जिससे अंबेडकर जी का गौरव और बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी डॉ. अंबेडकर जी के विजन के अनुसार समाज के हर वर्ग की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक स्थानीय स्कूल के सालाना इनाम वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश बहुत तेजी से एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और इस तरक्की में शिक्षा भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य के नेता हैं और सरकार देश के बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि हमारा देश टेक्नोलॉजी, डिफेंस और साइंस के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी

प्रत्येक महिला को सशक्त बनाना, प्रत्येक समुदाय का उत्थान करना–अमृत काल में नारी शक्ति का नया दौर

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो राष्ट्र का उत्थान होता है। समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज में, महिला की गरिमा से कतई समझौता नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारे समग्र कार्यक्रम–मिशन शक्ति–के ज़रिए इसे संस्थागत ढांचे में बदलकर इस विश्वास को फिर से मजबूत किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही कहा है, फ्हमारी सरकार महिलाओं के लिए 'सम्मान' और 'सुविधा' को सबसे ज़्यादा महत्व देती है।'' ये मार्गदर्शक शब्द केवल भावनाएँ मात्र नहीं, अपितु वह नींव हैं, जिस पर मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति के तहत भारत के कोने–कोने में मज़बूत संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं।

इस प्रयास के केंद्र में मिशन शक्ति की फ्संबल'' उप–योजना के तहत चलने वाले वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) हैं। 2015 में शुरू हुए ये केंद्र हिंसा की शिकार महिलाओं को एकीकृत सहायता तंत्र प्रदान करते हैं, ताकि उन्हें खामोश रहकर पीड़ा न सहनी पड़े और न ही बिखरी हुई सहायता प्रणालियों के बीच भटकना पड़े। आज तक, पूरे भारत में 862 ओएससी चल रहे हैं, जिनसे 12.20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी मदद, चिकित्सा सहायता, पुलिस की मदद, आश्रय और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी एकीकृत मदद मिली है।

डर से आज़ादी तक, खामोशी से सहायता तक – ओएससी ऐसे स्थान हैं जहाँ से घाव भरने की शुरूआत होती है। ये केंद्र प्रतिक्रियात्मक शासन से आगे बढ़कर सक्रिय शासन का रुख करते हैं। चाहे किसी महिला को अपने घर, कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थान पर हिंसा का सामना करना पड़े, ओएससी उसके पुनर्वास, गरिमा और न्याय दिलाने में मदद करने के मोदी सरकार के संकल्प का प्रमाण हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केंद्र अस्पतालों के भीतर या उनके पास स्थापित किए गए हैं, ताकि तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके – जो मुश्किल समय में पहला ज़रूरी कदम है। महिला हेल्पलाइन (181) का सार्वभौमीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो संकट से घिरी महिलाओं के लिए 24×7 मदद सुनिश्चित करके ओएससी का पूरक बनता है। 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित यह हेल्पलाइन अब तक 2.56 करोड़ से अधिक कॉल संभाल चुकी है और 93.48 लाख से अधिक

महिलाओं की मदद कर चुकी है (30 सितंबर तक)। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस–112) से एकीकृत यह हेल्पलाइन संकट और राहत के बीच की दूरी को पाटती है।

व्यवस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने और तेजी से न्याय पहुंचाने के लिए, हमने 745 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं, जिनमें से 404 विशेष पॉक्सो न्यायालय हैं। इन न्यायालयों ने यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार नहीं है, अब तक 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। सुनाया गया प्रत्येक फ़ैसला, बहाल किया गया प्रत्येक अधिकार न्यायपूर्ण और लैंगिक समानता वाले भारत की ओर उठाया गया एक कदम है। न्याय मिलना अब प्रक्रियात्मक देरी के कारण बाधित नहीं होता, और प्रत्येक सर्वाइवर समय पर राहत की उम्मीद कर सकता है।

इसके साथ ही, हम पुलिस स्टेशनों पर 14,658 महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) के साथ ज़मीनी स्तर को मज़बूत कर रहे हैं, जिनमें से 13,700 से ज़्यादा की कमान महिलाएँ संभाल रही हैं। ये डेस्क सर्वाइवर्स में अपराधों की रिपोर्ट करने का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिन्हें महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील प्रशिक्षित कार्मिकों की सहायता मिलती है। महिला अधिकारियों की मौजूदगी न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि संस्थागत संवेदनशीलता और जवाबदेही को भी मज़बूत करती है।

हम 807 एंटी–ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एएचटीयू) के ज़रिए मानव तस्करी से भी निपट रहे हैं और निर्भया कोष के तहत रेलवे और सड़क परिवहन सेवाओं में आपातकालीन निगरानी प्रणालियों की स्थापना के जरिए सुरक्षित गतिशीलता सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कदम कि महिलाओं का सुरक्षित रूप से यात्रा करना, निडर होकर काम करना और सार्वजनिक एवं निजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करना सुनिश्चित करते हैं।

यह एकीकृत दृष्टिकोण सिर्फ़ प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम, पुनर्वास और सशक्तिकरण तक व्याप्त है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसी पहलों के ज़रिए, हम सोच बदल रहे हैं और सम्मान, बराबरी और अवसर के मूल्य स्थापित कर रहे हैं। पीएमएमवीवाई और सखी निवास के ज़रिए, हम ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जो महिलाओं को सिर्फ़ सर्वाइवर के तौर पर ही नहीं, बल्कि देश की प्रगति में हितधारकों के तौर पर भी महत्व देती हैं। हमारे सखी निवास हॉस्टल, जिनमें से कई शहरी प्रत्येक और अर्ध–शहरी इलाकों में हैं,– 26,000 से ज़्यादा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती रहने की जगह दे रहे हैं जिससे वे बिना किसी डर के अपने सपने पूरे कर सकती हैं।

मिशन शक्ति के तहत हमारी रणनीति एकीकरण, समन्वय और सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। संकल्पॱ हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ विमेन की शुरुआत के साथ, हमने स्थानीय क्रियान्वयन में एक रणनीतिक परत जोड़ी है, जिससे महिलाएँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कई योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण और समन्वय के केंद्र के रूप में कार्य करने वाले इन केंद्रों के ज़रिए 27 लाख से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सरोकार है। प्रत्येक निर्मित ओएससी, प्रत्येक हेल्पलाइन कॉल जिसका उत्तर दिया गया, और निपटाया गया प्रत्येक मामला, ऐसा भारत बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहाँ प्रत्येक महिला गरिमा, सुरक्षा और गर्व के साथ जीवन जी सके।

जैसे×जैसे हम अमृत काल ×भारत की प्रगति और बदलाव के स्वर्णिम दौर× में कदम रख रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ़ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। सशक्त महिलाओं को केंद्र में रखे बगैर 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न अधूरा है।

नारी शक्ति कोई नारा नहीं है। यह हमारी रणनीति है। यह हमारी ताकत है। यह हमारा भविष्य है। महिलाएं –देखरेखकर्ता, परिवर्तनकर्ता, उद्यमियों और नेतृत्वकर्ताओं के तौर पर – विकसित भारत की रीढ़ हैं। उन्हें सम्मान, सुरक्षा और अवसर देना सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

हमारा सफ़र जारी है, एक समय में एक सशक्त महिला, एक समय में एक सुरक्षित स्थान के साथ। और प्रत्येक कदम के साथ, हम एक मज़बूत, सुरक्षित और अधिक समावेशी भारत का निर्माण कर रहे हैं।

(लेखिका भारत सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं।)